Shri Sant Gadge Baba Hindi Mahavidyalaya, Bhusawal

Dr. RAMESH PRABHAKAR JOSHI

Principal, Shri Sant Gadge Baba Hindi Mahavidyalaya, BHUSAWAL, Dist. Jalgaon

Papers Published in Journal

Sr. No.	Name of Author	First Author or Second	Title of Paper	ISSN No.	Impact Factor Name and Marks	Publisher	National / International	Whether UGC Approved Yes /No	Whether Peer Reviewed Yes /No	Month and Year of Publication	Issue / Volume	Direct Link to Download
1	Dr. Ramesh Prabhakar Joshi	First	वैश्विक आर्थिक मंदी तथा उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पार हुए प्रभाव पृ. ९०-९२	ISSN-0974-2832		Shodh samiksha Aur Mulyakan International Reviewed	International		Peer-Reviewed	Mar-10		
2		First	भारत के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निदेश पृ. ५९-६१	ISSN-0974-2832	Impact Factor - 1.0060	Shodh samiksha Aur Mulyakan International Reviewed	International		Peer-Reviewed	Jan-14		
3		First	भारत में प्रादेशिक असंतुलन पृ. ४८५-४८९	ISSN-2349-4766	Impact Factor - 6.177	Scholarly Research Journal for interdisciplinary Studies	International		Peer-Reviewed	Dec-18		
4		First	Impact of GST on Indian Economy P.No. 44-45	ISSN-2348-7143	Impact Factor - 6.261	Research Journey International Multidisciplinary E-Research Journal	International		Peer-Reviewed	Feb-19		
5		First	Foreign Direct Investment P.no. 32-35	ISSN-2348-7143	Impact Factor - 6.261	Research Journey International Multidisciplinary E-Research Journal	International		Peer-Reviewed	Mar-19		

6		First	लघु और कुटीर उद्योगो कि स्थिति में सुधार पृ. १३९-१४२.	ISSN-2348-7143	Impact Factor - 6.261	Research Journey International Multidisciplinary E-Research Journal	International		Peer-Reviewed	April-June 2019		
7		First	Demonetization and its impact on Indian Economy P.no 217-218	ISSN-2319-8648	Impact Factor - 7.139	Current Global Reviewer International Peer Reviewed Refereed	International		Peer-Reviewed	Oct-19		
8		First	महात्मा गांधी के आर्थिक विचार पृ. २३-२५	ISSN-2348-7143	Impact Factor - 6.625	Research Journey International Multidisciplinary E-Research Journal	International		Peer-Reviewed	Feb-20		
9		First	भारतीय किसानों कि समस्या एवं उपाय पृ. ०३-०८	ISSN 2582-5429 (online)		Akshara Multidisciplinary Research Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal	International		Peer-Reviewed	Oct-Dec 2019		
10		First	ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ एवं समाधान पृ. ०९-१५	ISSN 2582-5429 (online)		Akshara Multidisciplinary Research Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal	International			Oct-Dec 2019		
11		First	भारत में महिलाओ का सक्षमीकरण पृ. २३१-२३४	ISSN-2348-7143	Impact Factor - 6.261	Research Journey International Multidisciplinary E-Research Journal	International		Peer-Reviewed	Mar-20		
12		First	कोविड-१९ भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पर होनेवाले परिणाम एवं उपाय पृ. ६९-७२	ISSN 2582-5429 (online)		Akshara Multidisciplinary Research Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal	International		Peer-Reviewed	April-June 2020	Vol-02 Issue-I (A)	

ISSN 2582-5429(online)
AMRJ Akshara Multidisciplinary Research Journal
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
April-June 2020 VOL. 02 | ISSUE. I (A)
कोरोना संकटाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, परिणाम व उपाययोजना
Indian Economy & CORONA Crisis: Effects Challenges & Remedies
www.aimrj.com
Email ID. aimrj18@gmail.com

टूरीझम ऱ्हास :-

कोवीड 19 के कारण भारत में टूरीझम (पर्यटन) उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। होटल, रेस्टॉरंट, एंजेट, गाईड, ट्रॅव्हल्स, हवाई यातायात आदि व्यवसायों में लगे लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त कर देनेवाली इंडस्ट्री है। परंतु संपूर्ण लॉकडाऊन के कारण टूरीझम में बेरोजगारी छायी हुई है। उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। यह आपदा ने इस उद्योग की कमर तोड दी है। लाखों नुकसान इस उद्योग ने उठाया है।

ग्राहकों में कमी :-

कोरोना लॉकडाऊन के कारण रोजगार पर बूरा असर होने का एक कारण ग्राहकों की मांग में कमी होना है। देशभर में संपूर्ण लॉकडाऊन के कारण सभी को घर पर ही रहना अनिवार्य हुआ है। जिससे उपभोक्ता मांग में भारी कमी आयी है। होटल, ठेलेवाले, छोटे व्यवसायी, रीक्षा, टॅक्सी जैसे कई छोटे छोटे व्यवसाय बंद है। इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। पूरे देश में 14 करोड से भी अधिक लोग बेरोजगार हुए है।

उपाय :-

मनरेगा :-

शहरों से बहुतांश लोग गाँवों की ओर पलायन कर चुके है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। अत: देश में मनरेगा जैसी रोजगार देने वाली योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना अनिवार्य है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये का पॅकेज की घोषणा की गयी है। इसमें मनरेगा पर भी अलग प्रावधान रखा गया है। ऐसी योजनाओ से कुछ हद तक रोजगार की समस्या को हल किया जा सकता है।

सुक्ष्म, लघु तथा बड़े उद्योगों को सहायता :-

भारत में अतिसूक्ष्म तथा लघु उद्योगों में रोजगार की क्षमता सर्वाधिक है। इस समय यह उद्योग बंद पड़े हुए है, जिससे रोजगार का प्रश्न विकट हुआ है। अत: केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इन उद्योगों को वित्तीय सहायता कर पॅकेज में सुविधा देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से यह उद्योग फिर से शुरू हो सकते है तथा कई लोगों को रोजगार दे सकते है।

स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा :-

वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने Vocal for Local का नारा दिया है। अर्थात हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो अपने प्रदेशों में तथा स्थानीय स्तरों पर स्थानीय उत्पादन की मांग करनी चाहिए जिससे स्थानिक लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। इस तरह से हमें स्थानीय उत्पादनों का आग्रह करना आवश्यक है।

आत्मनिर्भरता :-

प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आवश्यकताओं के लिए हमेशा दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना गलत होता है। यदि हमारा राष्ट्र अपनी आवश्यकताएँ अपने ही देश में पूरी कर लेता है, तो इससे दूसरे राष्ट्रों पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ अपने देश में अधिकांश लोगों को रोजगार दे सकता है। अत: रोजगार सृजन के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।

©Copyright 2020 AMRJ. All Rights Reserved

यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। उनके लिए अपनी रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हुई है। अधिक समय के लिए बेरोजगारी का शिकार होना बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है।

भूखमरी :-

भारत में असंघटित क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कार्यरत लोगों का रोजगार लॉकडाऊन के लंबे समय के कारण हाथ से निकल चुका है। उनकी रोजी-रोटी बंद हुई है। आय के अन्य स्रोत नहीं है। इसलिए बेरोजगारी के कारण उनके सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई है। लगभग 4 महिनों से वेतन नहीं है। व्यवस्थापन के द्वारा उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। कुछ लोगों की मौत भोजन न मिलने से हुई है। यह एक बड़ी त्रासदी है। यह बेरोजगारी का ही गंभीर परिणाम है।

पलायन :-

कोवीड 19 के कारण भारत में एक नई समस्या ने जन्म लिया है। असंघटित क्षेत्र के काम करनेवाले अधिकांश लोग बाहर गांव या राज्य से आते है। ''बड़े-बड़े शहरों में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में काम करनेवाले मजदूर रोजगार क अभाव में अपने अपने गाँवों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हुए है।''[3] लॉकडाऊन के कारण वे साधनों के अभाव में पैदल ही निकल पड़े है। उनकी इस अवस्था को देखकर बड़ा ही दुख होता है।

कुछ लोगों ने अपने सफर में ही दम तोड़ दिया है। कडी धूँप में परिवार के साथ चल रहे है। वे अत्यंत असहाय है, मजबूर है। इस तरह की पलायन की भावना के कारण लॉकडाऊन खूलने के बाद उद्योगों में छोटे-छोटे व्यवसायों में मजदूरों की कमी की समस्या एक नया संकट पैदा कर सकती है। असुरक्षितता के कारण मजदूरों का गाँव से वापिस आना कठीन हुआ है। इस तरह से एक समस्या ने दूसरी समस्या को पैदा कर दिया है। यह घर वापसी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 50 लाख के आसपास यह संख्या है।

आय की कमी :-

भारत में विगत 2-3 महिनों के लॉकडाऊन के कारण सर्वत्र महामंदी जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। उद्योगों के व्यवस्थापन द्वारा श्रमिकों का वेतन देना बंद कर दिया है। असंघटित क्षेत्र के मजदूरों पर यह बहुत बड़ी मार है। मजदूरों को असहाय छोड़ दिया गया है। परिणाम स्वरूप आय के स्रोत बंद हुए है। वेतन के अभाव में परिवार के भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हुई हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी होने की समस्या निर्माण हुई है।

रोजगार छँटनी :-

भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना संकट ने एक गंभीर समस्या को निर्माण किया है। अखबारों के आँकडे बताते है कि, ''जो भारतीय विदेशों में अलग-अलग व्यवसायों में कार्यरत है, उनमें से लगभग 3 से 4 लाख लोगों अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है।''[4] अर्थात कई कंपनियों ने श्रमिकों की कटौती का फैसला लिया है। भारत में भी कई उद्योगों में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। असंघटित क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गहरी है। ऐसी स्थिति में भारत में बेरोजगारी का गंभीर रूप देखने को मिल सकता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है।

ISSN 2582-5429(online)
AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research Journal
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
April-June 2020 VOL. 02 | ISSUE. I (A)

श्रमिकों का पुर्नवसन :-

कोरोना के कारण श्रमिकों ने रोजगार के अभाव में अपने पैतृक गाँवों की ओर वापसी की है। अब गाँवों में बेरोजगारों की समस्या गंभीर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ऐसे श्रमिकों का उचित पुनर्वसन करने की आवश्यकता है। श्रमिकों को वित्तीय सहायता देकर फिर से उन्हें रोजगार के स्थानों पर स्थापित करना आवश्यक है।

श्रमिको का निर्वाह वेतन :-

वर्तमान स्थिति में श्रमिकों का रोजगार छीन गया है तथा हाथ में पैसा नहीं है। परिणामस्वरूप उनके सामने भूखमरी का प्रश्न पैदा हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार द्वारा श्रमिकों के खातों में एक निर्धारित राशि निर्वाह वेतन के रूप में जमा करना आवश्यक है। जन धन के तहत अथवा उनके बचत खातों में यह राशि जन्म करके उन्हें राहत पहूँचाना जरूरी है।

ऋणों की सहायता :-

कोरोना के कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। सभी उद्योग, व्यवसाय तथा छोटे-छोटे असंघटीत उद्योग करनेवालों से समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। अपने कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है। ऐसी स्थिति में बँकों द्वारा इन उद्योगों को आवश्यकता के अनुसार अत्यंत अल्प ब्याजदरों पर ऋण उपलब्ध कर देना आवश्यक है। उनके ऋणों की सरकार द्वारा ग्यारंटी लेना आवश्यक है। ऐसा करने से वे फिर से खड़े होगें और रोजगार का सृजन करेंगे।

इन उपायों के अलावा देश का निर्यात बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, साधनों की उपलब्धि बढ़ाना, कृषि में सुधार लाना ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों द्वारा इस संकट को दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष :-

हमारे प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देकर Vocal for Local और Local to Global का नारा दिया है। कोरोना के संकट की इस घड़ी में हम सभी को एक-दूसरें को सहयोग करते हुए रोजगार के सृजन के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाने होगें। नई शिक्षा नीति, नई उद्योग नीति तथा नई रोजगार नीति के साथ निर्णय लेने होंगे। कोरोना के साथ सुरक्षितता को ध्यान में रखकर फिर से नई उम्मीद लेकर देश का पुनर्निर्माण करना होगा।

संदर्भ सूची :-

1. नई दुनिया - दैनिक वर्तमान पत्र, 16 मई 2020
2. लोकसत्ता, दैनिक वर्तमान पत्र, 15 मई 2020
3. Times of India, 16 May 2020
4. लोकसत्ता, दैनिक वर्तमान पत्र, 30 मई 2020

©Copyright 2020 AMRJ. All Rights Reserved

Quarterly

(12)

ISSN 2582-5429 (online)

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

April-June 2020 Vol.02 ISSUE. I (A)

कोरोना संकटाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, परिणाम व उपाययोजना

Associate Editor

Mr. S. T.Dhum

Detp. Of Economies
Bhusawal Arts, Science &
P. O. Nahata Commerce College,
Bhusawal

Executive Editor

Dr. A. D. Goswami

Vice Principal
Bhusawal Arts, Science &
P. O. Nahata Commerce College,
Bhusawal

Guest Editor

Dr. Mrs.M. V. Waykole

Principal
Bhusawal Arts, Science &
P. O. Nahata Commerce College,
Bhusawal

Chief Editor : Dr. Girish S. Koli , AMRJ, Yawal
For Details Visit To – www.aimrj.com

Akshara Publication

के लिए नारी शक्ति को सशक्त करना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि, जब महिलाओं की स्थिति में उचित सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।

संदर्भ

1. योजना , अक्टूबर 2018 पृ. 07
2. योजना , अक्टूबर 2018 पृ. 09
3. कुरुक्षेत्र, जुन 2018 पृ. 45
4. योजना , अक्टूबर 2018 पृ.19
5. कुरुक्षेत्र, जुन 2018 पृ.14
6. योजना , अक्टूबर 2018 पृ.11
7. योजना , अक्टूबर 2018 पृ.20
8. योजना , सितंबर 2016 पृ.20
9. आर्थिक समीक्षा 2017–2018 पृ.45

ISSN 2582-5429(online)

AMRJ

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer Reviewed & Refereed International Research Journal

April-June 2020 VOL. 02 | ISSUE. I (A)

कोरोना संकटाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, परिणाम व उपाययोजना
Indian Economy & CORONA Crisis: Effects Challenges & Remedies

www.aimrj.com
Email ID. aimrj18@gmail.com

कोवीड-19 भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पर होनेवाले परिणाम एवं उपाय

प्रा. डॉ. रमेश प्रभाकर जोशी
सहयोगी प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख
श्री संत गाडगे बाबा हिंदी महाविद्यालय, भुसावल, जि. जलगाँव (महाराष्ट्र)
मो.क्र. 9975139141 ईमेल- rameshjoshi1965@gmail.com

सारांश :- भारत में कोरोना बीमारी की दस्तक 20 जनवरी 2020 में केरल राज्य में पहला पेशेंट मिलने से हुई। कोरोना की यह यात्रा चीन के वुहान शहर से शुरू हुई है। उसके बाद समूचे विश्व में हडकंप मची है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न राष्ट्र अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया जैसे राष्ट्रों में इस बीमारी ने त्राहीमाम कर दिया है। पूरे विश्व में अबतक तीन लाख से भी अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया है। 45.49 लाख लोग इस बिमारी से मृत्यू से जूझ रहे है। ऐसी प्राणघाती आपदा ने सारे विश्व को लॉकडाऊन में डाल दिया है। ``विश्व के बड़े 10 देशों में 2.42 लाख लोगों ने मृत्यू को गले लगा लिया है। भारत में भी लगभग 1 लाख से उपर लोग इस बीमारी का शिकार हुए है तथा 4 हजार के लगभग लोगों की मृत्यु हुई है।``[1] इसका बहुत बड़ा बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर हुआ है। अर्थव्यवस्था रूक-सी गई है। सर्वत्र बेरोजगारी फैल चुकी है। इस आपदा से लड़ना एक चुनौती बनी हुई है।

की-वर्डस :- कोवीड-19, लॉकडाऊन, अर्थव्यवस्था, कोरोना, आपदा।

प्रस्तावना :-

कोवीड 19 महामारी के इस संकट ने विश्व के सभी देशों को असहाय कर दिया है। इस बीमारी की कोई भी दवाई आज किसी भी देश के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए केवल लॉकडाऊन के सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ रूकी हुई है। मानों महामंदी का दौर चल रहा है। सभी उद्योगों में उत्पादन बंद हुआ है। परिणामस्वरूप इसकी बहुत बड़ी चोट रोजगार को बैठी है। उत्पादन बंद होने के कारण रोजगार नहीं है। कुछ आय ही सेक्टर में छुटपुट कार्य ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम के जरिए हो रहे है। लेकिन अन्य सभी उत्पादन लगभग बंद ही है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या ने उग्ररूप धारण कर लिया है।

समूचे ``भारत में लगभग 25 % से अधिक बेरोजगारी पायी जा रही है।``[2] बेरोजगारी की चपेट में विकास की अत्यंत नीचले स्तर पर आयी है। कोवीड 19 के रोजगार पर होने वाले प्रभाव को निम्न तरह से समझा जा सकता है :

रोजगार का छूट जाना :-

एक अनुमान यह है कि भारत में लगभग छः लाख लोगों ने अपने रोजगार को गवाया है। अर्थात करीब 25 % से भी अधिक बेरोजगारी पायी जा रही है। कोवीड 19 के कारण अचानक लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। यह एक अत्यंत क्लेशदायक घटना है। ऐसे बेरोजगारों के सामने एक बड़ा

©Copyright 2020 AMRJ. All Rights Reserved

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

महिलाओं की सुरक्षा

महिलाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक सुरक्षा देने की जरूरत है। कार्यस्थल को महिला कर्मचारियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संबंधित कानून 2013 को सख्ती से लागू किया गया है। इस कानून के तहत अब महिलाएँ बिना डरे रोजगार के लिए बाहर निकल रही है। इस कानून के तहत सभी प्रकार की महिलाएँ शामिल है। शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है ताकि आसानी से महिलाएँ शिकायत दर्ज कर न्याय प्राप्त कर सके। इसके अलावा महिला पुलिस बल से 33 फीसदी आरक्षण का नियम लागू किया जा रहा है। पूरे देश में 181 महिला हेल्पलाइन केंद्र को मंजूरी दी गई है।

महिला मुद्रा योजना

महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक मदत करने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया है। जिसमें महिलाओं को छोटे व्यवसाय करने जैसे टेलरिंग इकाई, ब्यूटीपार्लर, ट्यूशन सेंटर आदि व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की जाती है। "महिलाएँ समूह में भी यह ऋण किसी भी जमानत राशि के प्राप्त कर सकती है। 50, 000 से 10 लाख रुपए तक की ऋण राशि महिलाएँ प्राप्त कर सकती है।"[7] इससे महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिल सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

भारत में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की है। यह शीर्ष संस्था है जो, 'अनुसूचित जनजाति महिला सशक्तिकरण योजना'
(एएमएसवाई) के नाम से पेश की गई है। इस योजना के द्वारा निगम 1लाख तक की योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह 4 % दर पर दी जाती है। इससे बडे पैमाने पर महिलाओं को लाभ पहूँचा है।

संपत्ति का अधिकार

"1956 में हुए संशोधन ने महिलाओं को माता–पिता और ससुराल दोनों की संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार दिया है।"[8] इससे पूर्व महिलाओं का संपत्ति पर सीमित अधिकार होता था। कई जनजातीय कानूनों तथा धार्मिक कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को समुदाय से बाहर विवाह करने पर उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन अब यह संपत्ति का अधिकार प्राप्त होने से महिलाओं की स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है।

पंचायती राज

"संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।"[9] महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह बड़ी पहल होगी। तथा बहोत बडी क्रांति साबित होगी। पंचायती राज के कारण राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार आया है। यह नई चेतना का सूत्रपात हुआ है।

निष्कर्ष

महिलाओं के हितों की रक्षा करना और उनको सशक्त बनाना यह हमारे समाज की सामुदायिक जिम्मेदारी है। किसी भी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। महिलाएँ समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। वर्तमान समाज को सुदृढ करने

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योज़ना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योज़ना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

E-ISSN : 2348-7143
Jan-Feb-March 2020

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्थां योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताऐं प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलाये घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा समव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलाये घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलाये घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे मे बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लडकियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताऐं प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योज़ना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढा है।"[6]

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

'RESEARCH JOURNEY' International E- Research Journal
Impact Factor - (SJIF) - 6.625 (2019)
Vol. 7, Issue 1
Peer Reviewed Referred & Indexed Journal
E-ISSN : 2348-7143
Jan-Feb-March 2020

(11)

भारत मे महिलाओं का सक्षमीकरण

प्रा.डॉ. रमेश प्र. जोशी
असोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
श्री संत गाडगेबाबा हिन्दी महाविद्यालय, भुसावल, जिला जलगाँव

सारांश

देश की आजादी के बाद संविधान के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दिया है। भारत मे निरंतर रूप से महिलाओं को आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र मे एक समान दर्जा देने के उद्देश्य से कई उपाय किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को अपनी प्रतिभा दर्शाने एवं राष्ट्रीय गतिविधियो मे सहभागिता के लिए कई अवसर प्राप्त हुए हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी गई विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं के विकास के द्वार खोल दिए हैं। महिलाओं को समान दर्जा देने का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम समाज की निर्मिती करना है। ऐसा कहा जाता है कि, लैंगिक समानता ही सुशासन की कुंजी है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं उस देश की महिलाओं मे परिलक्षित होती है। महिलाएँ आज विश्व मतदाताओं का आधा हिस्सा बन चुकी है।

उद्देश्य–

1. भारतीय महिलाओं की स्थिति का आकलन करना।
2. महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना।

मान्यताएँ–

1. भारत मे महिलाओं की स्थिति कमजोर है।
2. आर्थिक विकास मे महिलाओं का योगदान निम्न है।
3. महिलाओं के लिए योजनाएँ कम है।

संशोधन पद्धती –

प्रस्तुत लेख मे अध्ययन के लिए द्वितीयक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है। विभिन्न ग्रंथों एवं शोध पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है।

प्रस्तावना–

महिलाओं की उद्यमशीलता परिवारों तथा समुदायों के आर्थिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दे सकती है। महिलाएँ स्वयं तथा दूसरो के लिए रोजगार एवं अपने आय का सृजन कर सकती है। वह आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है। समाज की कई समस्याओं का समाधान करने मे सक्षम साबित हो सकती है। भारत की कुल आबादी मे महिलाओं का योगदान लगभग आधा हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक जीवन मे महिलाओं की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। नौकरशाही, दफ्तरो में कामकाज, राजनीति, स्व-रोजगार, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय खेल जगत एवं अन्य क्षेत्रों मे महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ रहा है। यह बदलाव स्वागत करने के योग्य है। कई क्षेत्रों मे महिलायें देश के लिए मिसाल बन चुकी है। महिलाओं में सृजन, पोषण और परिवर्तन की क्षमता है। भारतीय संस्कृति मे नारी शक्ति का महत्व अनंत काल से मौजूद रहा है। नारी का अलग–अलग रूपों मे पूजन होता आ रहा है। " यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते। रमन्ते तत्र देवता" यह धारणा चली आ रही है। हालाकि यह एक तस्वीरें है। दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण है । परंतु हाल के वर्षों मे महिलाओं के जीवन मे महत्वपूर्ण

बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सरकार की भूमिका अहम है। "देश की कुछ आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। ऐसे में बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना यात्रा संभव नहीं हो सकती।"[1]

भारत में महिलाओं को सक्षम करने हेतु उठाए गए कदम

वित्तीय सहायता–

महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। "सन 2005–06 में बैंक या बचत खाता रखने वाले महिलाओं की मात्रा केवल 15 प्रतिशत थी। जो बढकर 2015–16 में 53 फिसदी हो गई।"[2] सन 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। इस राशि को लड़की के 18 साल पूरा करने पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक कुल 1.39 करोड लड़कियों के खाते खोले जा चुके हैं। जिसमें 25979 करोड रुपए जमा हुए। जनधन योजना के तहत 16.42 करोड महिलाओं के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी महिलाओं ने अच्छी सफलता हासिल की है। सन 1950–1951 महिलाओं की औसत आयु 31.7 थी जो 2016 में बढ़कर 70 साल हो गई है। अब ज़्यादातर महिलायें घर की बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म देना उचित समझ रही है। यह बच्चा तथा माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुआ है। इससे मातृत्व मृत्यु दर भी घटी है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत नगद धन राशि दी जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए करीब 10,31805 आशा कार्यकर्ता और 220707 सहायक नर्स (दाई) कार्यरत है। अस्पताल जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है। 1.35 करोड महिलाओं ने अब तक यह लाभ उठाया है। इसके अलावा शिशु टीकाकरण, गर्भावस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे कई कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना

"महिलाओं में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया है।"[3] विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार (स्टेप) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। "यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण , पर्यटन, कंप्यूटर आय.टी. सेवाएँ जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षताएँ प्राप्त होगी। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड तक ऋण भी दिया जाता है।"4

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को अपने परिवार में काफी काम करना पड़ता है। जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं मिलता और इन कामों को मान्यता भी नहीं मिलती। "सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम करने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई है।"[5] इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। "जुलाई 2018 तक 5. 8 करोड से भी ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की समय की बचत होने से उनका उत्पादन कार्य बढ़ा है।"[6]

Impact Factor – 6.625

E-ISSN – 2348-7143

ISSN-2582-5429 (Online)

Akshara

Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

VOL. 1 | ISSUE. II | Octomber-Decmeber 2019

Chief Editor
Dr. Girish S. Koli
Dongar Katora, Tal. Yawal,
Dist. Jalgaon (M.S.) India.425301

Website : www.aimrj.com
Email ID : aimrj18@gmail.com

(11)

Impact Factor – 6.625

E-ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

International E-Research Journal

Peer Reviewed-Referred & Indexed Journal

January-February-March 2020

Vol.-7 Issue-1

Chief Editor -
Dr. Dhanraj T. Dhangar,
Assist. Prof. (Marathi)
MGV'S Arts & Commerce College,
Yeola, Dist – Nashik [M.S.] INDIA

Executive Editors :
Prof. Tejesh Beldar, Nashikroad (English)
Dr. Gajanan Wankhede, Kinwat (Hindi)
Mrs. Bharati Sonawane-Nile, Bhusawal (Marathi)
Dr. Rajay Pawar, Goa (Konkani)

This Journal is indexed in :
- University Grants Commission (UGC)
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION

AMRJ
ISSN 2582-5429(online)
Akshara Multidisciplinary Research
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
www.aimrj.com
VOL.I | ISSUE.II | October-December 2019
Email ID. aimrj18@gmail.com

प्रस्तावना

किसान हमारे देश के लिए वैसी ही भूमिका निभाता है जैसा कि मानव शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी निभाता है। समस्या यह है कि यह रीढ़ (हमारे किसान) कई समस्याओं से पीड़ित है। कभी–कभी उनमें से कई एक दिन में दो समय का भोजन भी नहीं कर सकते है। सभी कठिनाइयों के बावजूद जो वें सामना करते हैं, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से पहले भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन करने में सक्षम नहीं था। दूसरे शब्दों में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। हम विदेशों से (मुख्य रूप से अमेरिका) बडी मात्रा में खाद्यान्न आयात करते थे। यह कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन बाद में यूएसए ने हमें व्यापार पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था।

इस स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने चुनौती स्वीकार की और 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया और कुछ कठोर उपाय के किए जिनके परिणामस्वरूप हरित क्रांति आई और उसकी वजह से हम आत्मनिर्भर हो गए। आज किसान अधिशेष उत्पादन करता है लेकिन दूसरी ओर उसकी हालत बुरी बनी हुई है। कृषि एक विज्ञान है जिसमें फसल उगाने से लेकर उसके बाजारीकरण तक का सूक्ष्म ज्ञान निहित है।

किसानों की समस्याएँ

- समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 3 लाख (सरकारी अनुमान) किसानों ने 1995 से आत्महत्या की है। इन आत्महत्याओं का मुख्य कारण किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने में असमर्थता है। उसके द्वारा विभिन्न कारणों से यह ऋण लिए गए हैं। इस सूची में अव्वल रहने का संदिग्ध भेद महाराष्ट्र को जाता है।
- एक अन्य अनुमान (सरकारी डाटा) के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत किसान कर्ज में है और अधिकतम गरीब है। कई किसान गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर है। उनकी अवसर औसत वार्षिक आय 21 हजार रूपये से भी कम

ISSN 2582-5429(online)
AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
VOL.1 | ISSUE.II | October-December 2019
www.aimrj.com
Email ID. aimrj18@gmail.com

भारतीय किसानो की समस्या एवं उपाय

प्रा.डॉ. रमेश प्र. जोशी
असोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
श्री संत गाडगेबाबा हिन्दी महाविद्यालय, भुसावल, जिला. जलगाँव

सारांश :–

किसीने सही कहा है, "भारत गाव की भूमि है और किसान देश की आत्मा है।" भारत किसानों की भूमी है। इसे इस लिए कहा जाता है क्योंकि, अधिकांश भारतीय प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से कृषि गतिविधियों में शामिल होते है। यह कहना गलत नही होगा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे देश में खेती को एक महान पेशा माना जाता है। उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। जिसका अर्थ है, "अन्न देनेवाला।" इस तर्क के अनुसार भारत में किसानों को एक खुशहाल और समृध्द होना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि वास्तविकता इसके विपरीत है। किसानों में ऋणग्रस्तता, निर्धनता, उचित दामों का अभाव, लागतें अधिक सिंचाई की कमी तथा सरकार का दुर्लक्ष जैसी कई समस्याएँ गंभीर बनी हुई है। अतः हमें समय रहते इन समस्याओं को खत्म कर लेना चाहिए। अन्यथा गंभीर संकट का सामना करना पड सकता है।

की वर्ड्स :–

NAAM, ऋणग्रस्तता, बाजारीकरण, प्रीमियम, उन्मूलन, इरिगेशन आदि

उद्देश्य :–

1. भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. किसानों की समस्याओं का पता रखना।

मान्यताएँ :–

1. भारतिय किसान अत्यंत निर्धन है।
2. भारतिय किसानों में आत्महत्यायें अधिक है।
3. भारतिय किसानों की ऋणग्रस्तता अधिक है।

ISSN 2582-5429(online)
AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
VOL.1 | ISSUE.II | October-December 2019
www.aimrj.com
Email ID. aimrj18@gmail.com

है, यही कारण है कि किसान खेती छोड़ रहा है और अन्य व्यवसाय में जाने की कोशिश कर रहा है।

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी की जलवायु बदल रही है । बाढ़ और सूखे की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ी है, जिसमें बड़े पैमाने पर फसल क्षति होती है। यह एक प्रमुख कारण माना जाता है। मानसून की अनियमितता यह किसानों के लिए खतरे की घंटी है। उसके लिए निर्णय करना कठिन है।
- अधिकतम किसान बारिश पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उनके पास सिंचाई के उचित साधन नहीं होते हैं। जैसे डीजल पंप सेट, नहर या बांध का पानी आदि। इसका मतलब है कि अगर यह खराब मानसून है तो उनकी फसल खराब होगी। आज भी केवल 20 से 22 प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यह एक चिंता का विषय है।
- भारत में कृषि भूमि के जोत का आकार छोटा होना यह भी एक यह प्रमुख समस्या मानी जाती है। भारत में अधिकांश किसानों के पास भूमि के छोटे से बहुत छोटे भूखंड है जिस पर वे खेती करते हैं। जिससे कृषि भूमि लाभहीन बनी हुई है। ऐसे छोटे टुकड़ों पर यांत्रिक खेती करना संभव नहीं होता। इसलिए उसकी उत्पादकता निम्न है।
- अन्य व्यवसाययों की भाँति खेती को भी निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन यह गरीब किसानों के पास नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति और कागजी कार्यवाही अधिक है । इसलिए किसानों को साहूकार या अन्य बड़े व्यापारी के पास उधार लेने के लिए जाना पड़ता है जिनकी ब्याज की दरें ऊँची होती है। जिसको चुकाना बड़ा कठिन होता है।
- वैश्वीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, WHO आदि का भी भारतीय कृषिपर विपरीत प्रभाव हो रहा है। विकसित तथा अविकसित देशों की कृषि नीति में अंतर है। विकसित देशों में कुछ कृषि फसल की कीमत पर 32 से 37 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। जापान में 70 प्रतिशत, कनाडा में 33 प्रतिशत, यूरोप 30:

ISSN 2582-5429(online)
AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
VOL.1 | ISSUE.II | October-December 2019
Email ID. aimrj18@gmail.com
www.aimrj.com

- ✓ किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें भारतीय कृषि में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। अधिकांश कृषि भूमि असिंचित है। उचित नियोजन के माध्यम से स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा फसलों को सिंचित करने से अवश्य ही उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की स्थितियों में सुधार होगा।
- ✓ वर्तमान सरकार द्वारा 2022 तक किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार ने 50,000 करोड रू. व्यय का लक्ष्य रखा है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं। E-NAAM के द्वारा सभी कृषि मंडियों को आपस में जोड़ दिया गया है। इसे अवश्य ही किसानों को लाभ होगा।
- ✓ सभी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को उचित लाभ होगा। खासतौर पर दालों के समर्थन मूल्यों में वृध्दि की गई है। इस समर्थन मूल्य से नीचे की खरीदी को अपराध माना जाएगा। यह एक अच्छा कदम होगा।
- ✓ बिजली से वंचित गाँवों में बिजली पहुँचने हेतु एक व्यापक मिशन चलाया जा रहा है। इससे किसानों को पर्याप्त समय के लिए बिजली मिलेगी और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- ✓ किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए दूरदर्शन से अलग–अलग से किसान चैनल की शुरुआत की है। इंटरनेट, मोबाइल विभिन्न एप्स आदि के द्वारा किसानों की उनकी फसल के उचित मूल्य मिल पाएंगे और उनकी स्थिति में अवश्य सुधार होगा।
- ✓ कृषि के प्रति आकर्षण पैदा करना और कृषि आधारित उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना। कृषि को व्यवसाय के स्तर पर चलाने से उसकी लाभदायकता बढ़ेगी। इस व्यवसाय अच्छी प्रतिष्ठा मिलने से किसानों को लाभ होगा।

ISSN 2582-5429(online)
Akshara Multidisciplinary Research
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
VOL.1 I ISSUE.II I October-December 2019
www.aimrj.com
Email ID: aimrj18@gmail.com

प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। लेकिन भारत में केवल 3 प्रतिशत अनुदान मिलता है। इस बात का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

- मुक्त आयात नीति के कारण भी किसानों को नुकसान पहुँच रहा है। 1435 कृषि वस्तु पर लगाए वह नियंत्रण हटाए गए हैं। कोटा पद्धति को निरस्त किया गया है। आयात शुल्क कम करने से विदेशी आयात बढ़ा है। काजू, विभिन्न फल, रसायन आदि कृषि वस्तुओं का आयात बढ़ने से उसका कीमतों पर विपरीत परिणाम हुआ है। इसके अलावा उचित बीमा का अभाव, भ्रष्टाचार, नई तकनीक का अभाव आदि कई कारणों से भारतीय किसानों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

किसानों की दशा में सुधार के उपाय :-

- ✓ यदि किसानों की स्थिति में सुधार लाना है तो उन्हें नियमित तथा समय पर आर्थिक सहायता के लिए आसान ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। सस्ता ऋण तथा अनुदान मिलने से उनकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और अच्छी गुणवत्ता, बीज, खाद्य खरीदने में सक्षम होंगे।
- ✓ किसानों की फसल कई कारणों से खराब हो जाती है इसलिए किसानों को उचित विमा सुविधाएँ देना काफी फायदेमंद होगा। यह बेहतर होगा कि सरकार द्वारा अधिकांश या पूरे प्रीमियम का भुगतान किया जा सके क्योंकि कई किसान गरीब है और वें प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते।
- ✓ आज भी कृषि विपणन व्यवस्था में कई दोष विद्यमान है। बाजार में दलाल, अडतियें, व्यापारी इन मध्यस्थों का प्रभाव बढ़ा है। जो किसानों को लाभ पहुँचने नहीं देते। इनका उन्मूलन होना आवश्यक है। प्रत्यक्ष किसान तथा सरकार के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए। आधुनिक तंत्र का उपयोग कर दामों का निर्धारण होना चाहिए। मोबाइल का उपयोग किसानों के लिए फायदेमंद होगा।

ISSN 2582-5429(online)
AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
VOL.1 | ISSUE.II | October-December 2019
www.aimrj.com Email ID. aimrj18@gmail.com

- ✓ कृषि के व्यापक विकास के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषक नीति लाई गई है। इसके तहत कृषिकों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए APMC एक्ट भी लाया गया है। कृषि में अनुसंधान एवं विकास के उपायों को अपनाया गया है। इस दिशा में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' एक और नई पहल है।

निष्कर्ष

हम आजादी के बाद एक लंबी दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। यदि किसानों के महत्व को ध्यान में रखकर ईमानदारी से काम करते हैं यदि किसानों तो हम उन सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे, जो हम आज का सामना कर रहे हैं। हम सभी के प्रयासों से एक दिन हमारे भारतीय किसान भी उतने ही समृद्ध हो जाएंगे जितना कि अमेरिकी किसान अब है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु विगत कुछ दशकों से सरकार की गलत नीतियों से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी। किसान हमारे अभिन्न अंग हैं। केवल बहस करने से काम नहीं होगा। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, लाभकारी फसलों की ओर खेती को मोड़ना, पूरक एवं प्रकियावाले उद्योगों का निर्माण करने हेतु निवेश को बढ़ावा देना होगा। तभी सुजलाम् सुफलाम् का स्वप्न पूरा होगा।

संदर्भ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था– रूद्रदत्त एवं सुंदरम, सन 2018 चाँद प्रकाशन, नई दिल्ली
2. योद्धा किसान–शरद जोशी
3. कृषि अर्थशास्त्र–डॉ. कवि मंडन
4. योजना –जनवरी 2010
5. द हिंदू– 4 जुलाई 2012

ISSN 2582-5429(online)

AMRJ

Akshara Multidisciplinary Research

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

VOL.1 | ISSUE.II | October-December 2019

www.aimrj.com

Email ID. aimrj18@gmail.com

Index

Sr.No	Title of the Paper	Author's Name	Page No.
1	भारतीय किसानो की समस्या एवं उपाय	प्रा.डॉ. रमेश प्र. जोशी	03-08
2	ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ एवं समाधान	प्रा.डॉ. रमेश प्र. जोशी	09-15
3	बिल्लु शेक्सपियर : पोस्ट बस्तर' में चित्रित आदिवासी विमर्श	डॉ. गिरीश एस. कोळी	16-19
4	अल्मा कबूतरी उपन्यास में नारी विमर्श	डॉ. मनोज एन. पाटील	20-24
5	आदिवासी केन्द्रित उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय	डॉ. जगदीश चव्हाण	25-29
6	सुनीता जैन काव्य में स्त्री विमर्श	कु. प्रियंका जगदीश महाजन	30-34
7	प्रिया तेंडूलकरांच्या कथांमधील स्त्रीवादी दृष्टिकोन	प्रा.डॉ. सुधा मधुकर खराटे	35-38
8	प्रतीमा इंगोले यांच्या कवितेतील स्त्रीवादी दर्शन	प्रा.सचिन दत्तात्रय पंडित	39-42

AIMRJ Disclaimer :

For the purity and authenticity of any statement or view expressed in any article. The concerned writers (of that article) will be held responsible. At any cost member of Akshara's editorial Board will not be responsible for any consequences arising from the exercise of Information contained in it.

क्षेत्र की नौकरियाँ कम होती जाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में गांधीजी के आर्थिक विचार अधिक उपयुक्त प्रतित होते हैं। आज कौशल भारत जैसे कार्यक्रम इस संकलना पर आधारित है।

➢ गांधीजी का मुख्य विरोध मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण किए जाने से था। इसलिए वे मशीनों और स्वचालन पर आपत्ति जताती है। उनका मानना था कि, पूँजी कुछ लोगों के श्रम का शोषण कर खुद को कई गुना बढ़ाती है। इससे धनिक और गरीब वर्ग के बीच की दूरी बढ़कर आर्थिक विषमता बढ़ेगी। समाज दो वर्गों में बट्टै जाएगा, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा। गांधीजी का गुलामी पर ऐतराज था।

➢ शिक्षा के बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण वस्तुतः व्यावसायपरक था। वह बुनियादी तालीम के पक्षधर थे। उनका मत था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ कुछ धनोपार्जन भी कर लेना चाहिए, जिससे वें आत्मनिर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 'वर्धा शिक्षा योजना' बनाई थी। शिक्षा को लाभदायक एवं अल्पव्ययी करने की दृष्टि से सन 1936 ई. में 'भारतीय तालीम संघ' की स्थापना की थी। आज की शिक्षा प्रणाली में होनेवाले परिवर्तन गांधी जी के विचारों पर आधारित है।

निष्कर्ष :

गांधीजी के विचार आधुनिकता पर निर्णायक विचार हो भी सकते हैं और नहीं, लेकिन उनकी नैतिक ताकत का प्रभाव अमीर लोगों पर भी पड़ रहा है। गांधीजी के मूल विचार, स्वदेशी, ग्रामम्य, गणतंत्र, कुटीर उद्योग, स्वयं–रोजगार, श्रम की गरिमा और धन की ट्रस्टीशीप आज की डिजिटल दुनिया के काल में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नैतिक सिद्धांत वैसे ही बदलाव लाए है, जैसी कि उन्होंने इच्छा की थी। किसी भी देश की उन्नति और विकास इस बात पर निर्भर होते हैं, कि वह देश आर्थिक दृष्टि से कितनी प्रगति कर रहा है तथा औद्योगिक दृष्टि से कितना विकास कर रहा है। आज भारतवर्ष का कौन ऐसा नागरिक है, जो महात्मा गांधी के नाम तथा राष्ट्र निर्माण में उनके कार्यकलाप से भलीभाँति अवगत नहीं है।

महात्मा गांधी उच्च कोटि के चिंतक थे। उनके बारे में विश्वविख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह मत है कि, हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ऐसा प्रकाशमान समकालीन पुरुष दिया है। यह भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश स्तंभ का काम देगा। गांधी जी क्रांतिकारी चिंतन आज भी सार्थक एवं अनुकरणीय है। भारत की आर्थिक, औद्योगिक व्यवस्था को लेकर गांधी जी का जो जीवन दर्शन देशवासियों को उपलब्ध हुआ, वह सदैव उपयोगी रहेगा।

संदर्भ :

1. Economic Thought of Mahatma Gandhi- M. Maharajan
2. ग्राम स्वराज्य एम. के. गांधी
3. महात्मा गांधी–सुमित्रा गांधी कुलकर्णी
4. योजना पत्रिका 2017–2018
5. कुरुक्षेत्र 2018–19

... Nagar, Bhusawal (02582) 225238
Fees Receipt

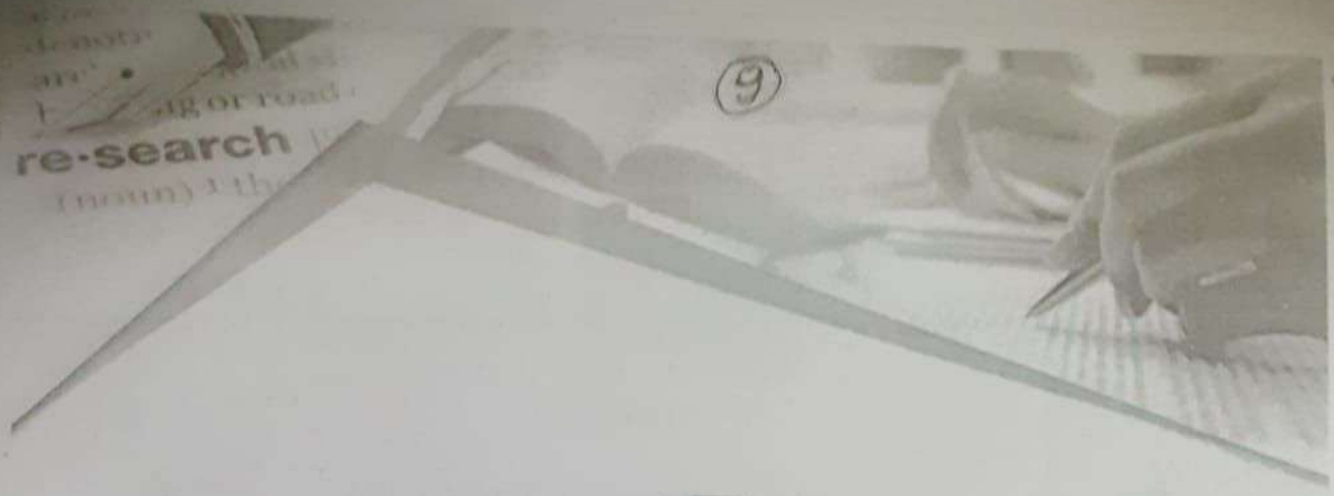

(9)

ISSN-2582-5429 (Online)

Akshara

Multidisciplinary Research Journal

— Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal —

VOL. 1 | ISSUE. II | Octomber-Decmeber 2019

Chief Editor
Dr. Girish S. Koli
Dongar Katora, Tal. Yawal,
Dist. Jalgaon (M.S.) India.425301

Website : www.aimrj.com
Email ID : aimrj18@gmail.com

'RESEARCH JOURNEY' International Multidisciplinary E- Research Journal | ISSN : 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) - 6.625. | February-2020
Special Issue 224 (E) : Relevance of Gandhian Thoughts
Peer Reviewed Journal

महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार

डॉ. रमेश प्र. जोशी
असोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
अर्थशास्त्र विभाग
श्री संत गाडगेबाबा हिंदी महाविद्यालय, भुसावल

सारांश :

समूचा विश्व आज विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। जिसमें पर्यावरणीय विभिषिकाओं, आतंकवाद, कुपोषण, विभिन्न संक्रामक बीमारियाँ आदि। पूरे विश्व में विकसित तथा विकासशील देशों में अंधी दौड़ लगी है। एक दौड़ उन लोगों की है जो संपन्न है, परंतु कुछ और पाने की लालसा में दौड़ रहे है। दूसरी ओर दूसरी दौड़ उन लोगों की है, जो दो समय की रोटी के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रहे है। ऐसे लोगों के लिए गांधी जी के विचारों अपरिग्रह और स्वराज्य का महत्व बढ़ जाता है। उनके मतानुसार इन सिद्धांतों के फलस्वरुप प्रत्येक राज्य सत्ता से स्वतंत्र होकर अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकेगा। साथ ही गाँव और ग्रामसभायें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सकेगी।

की वर्डस् : विभीषिकायें, कुपोषण, अपरिग्रह, स्वराज्य, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी आदि.

प्रस्तावना :

प्रस्तुत शोध लेख में महात्मा गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ पर आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था में गांधीजी के आर्थिक विचार कितने प्रासंगिक है, इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

लगभग एक शती पूर्व महात्मा गांधी जी ने कहा था कि, "हमारी धरती के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं।" इस बात पर कोई संदेह नहीं कि उनके यह विचार आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी का मूलमंत्र था कि तुम जब कोई भी काम करोगे, तो यह बात का ध्यान रखें कि इससे गरीब और कमजोर व्यक्ति को अवश्य लाभ होना चाहिए। यदि स्वराज्य के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते है और समावेशी विकास देखना पसंद करते हैं तो, हमें गांधीजी के इस मंत्र को अपने जीवन का आदर्श अवश्य बनाना होगा। गांधी जी की मूल कसौटी मानव मात्र की खुशी थी। उनका विचार था कि, प्रगति को मानवीय कल्याण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वह 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' और 'सर्वोदय' के सिद्धांतों में अधिक विश्वास करते थे। स्वराज्य के बारे में उनकी संकल्पना एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय हाथ में हाथ मिलाकर चल सके।

आर्थिक विचार :

- महात्मा गांधी जी का मानना था कि भौतिक प्रगति आवश्यक होनी चाहिए, वे इसका विरोध नहीं करते थे। उनका कहना था कि, मशीनों से सभी के समय और श्रम की बचत होनी चाहिए। वह नहीं चाहते थे कि, मनुष्य मशीनों का दास बनकर हो जाए अथवा वह अपनी पहचान ही समाप्त कर दे। उनका कहना था कि, मशीनें मनुष्य के लिए हो–ना–की मनुष्य मशीन के लिए हो।

➢ गांधीजी के मतानुसार आर्थिक समानता, अहिंसक स्वतंत्रता की असली कुंजी है। आजकल अत्याधिक उपभोग की अवधारणा को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है और स्वीकार किया जा रहा है, वह समस्त मानव समाज को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक अमीरों और करोड़ों भूखें लोगों के बीच की दूरी बनी रहेगी तब तक शासन की अहिंसक प्रणाली कायम करना संभव नहीं है। अन्यथा अलग–अलग प्रकार के सामाजिक संकट और विकार उत्पन्न होंगे।

➢ गांधीजी के नजरों में देखने पर हमें गाँवों को स्वावलंबी आर्थिक इकाइयों के रूप में बदलना होगा। निःसंदेह ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को उद्योगों की ओर मोड़ना होगा। लेकिन यह उद्योग छोटे या लघु उद्योग होंगे, जिनमें श्रमिकों के लिए अधिक काम मिलेगा और जो मुख्य रूप से गाँवों में ही स्थापित किए जाएंगे। हमारे गाँवों और छोटे शहरों को फिर से विकास का केंद्र बनाना होगा। समावेशी विकास के लिए हमें ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करें। गांधी जी हमारी धरोहर है, इसलिए हमें सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा हमारे नियोजन और विकास का केंद्र बना रहे।

➢ गांधीजी स्पष्टतया संपत्ति निर्माण के खिलाफ नहीं थे लेकिन वह सिर्फ निजी लाभ के लिए संपत्ति के असीमित प्रयोग के खिलाफ थे। उनके मतानुसार यदि मेरे पास एक उचित मात्रा में धन, व्यापार या विरासत के माध्यम से आता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि, जो मेरे पास है वह सारा मेरे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं है। जो मेरे पास है वह मेरी सम्माननीय आजीविका का अधिकार है। उस धन के शेष भाग पर समुदाय का अधिकार है और समाज के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। कई मायनों में ट्रस्टीशीप का विचार पश्चिम में प्रचलन में आ रहा है, अमेरिका के धनी उद्योगपतियों में एक शपथ लेने का प्रचलन बढ़ा है, जिसे वह 'द गिविंज प्लेज' कहते हैं। अर्थात वे अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान देते है। भारत में भी नारायणमूर्ति, अजीम प्रेम जी तथा शिव नाडर जैसे लोग परोपकार के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं।

➢ गांधीजी के मतानुसार देश की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। उनके मतानुसार विदेशी आयात को बाहर रखने से कहीं अधिक स्वदेशी का आचरण अधिक लाभकारी है। जहाँ कपास उगाने से लेकर सूत कातने तक के सभी कार्य एक ही गाँव या कस्बे में किए जाते हों, वहीं सच्चा स्वदेशी है। उनका मानना था कि, गाँव को गणतंत्र बनाने और उनके लोकतांत्रिक शासन के लिए उनका आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। गाँव के लोग अपने जरूरत की समस्त चीजें गाँव में पैदा कर सके। गांधीजी के मतानुसार जनता की गरीबी, आर्थिक और औद्योगिक परिक्षेत्र से स्वदेशी के बाहर हो जाने की वजह से हैं। उनके मतानुसार भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। इसलिए भारत को विकास मार्ग पर ले जाने के लिए ग्राम–विकास प्राथमिक आवश्यकता है।

गांधीजी शिक्षा से अर्थशास्त्री नहीं थे, किंतु इस विषय में भी उनका चिंतन क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा था कि अपनी जरूरत से अधिक संग्रह करने का अर्थ है–चोरी। उनके मतानुसार अर्थशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है। इंसान की कमाई का मकसद केवल सांसारिक सुख पाना ही नहीं, बल्कि अपना नैतिक और आत्मिक विकास करना था। इसलिए उन्होंने त्यागमय उपभोग का समर्थन किया है। वस्तुतः गांधी जी का आर्थिक चिंतन नैतिक आदर्शों पर समाजवाद का रामराज्य है। गांधी जी का मानना था कि, हर नागरिक को अपनी आजीविका 'शारीरिक परिश्रम' के द्वारा कमानी चाहिए।

➢ गांधीजी चाहते थे कि हमारा भविष्य अपने स्वयं के कौशल निर्माण स्वयंरोजगार आत्मउन्नति पर ही निर्भर है। वर्तमान स्वचालन, वैश्वीकरण और स्थानीयकरण की नई दुनिया में जहाँ औपचारिक

ISSN – 2348-7143

CURRENT GLOBAL REVIEWER

Special Issue 21, Vol. II | Peer Reviewed | ISSN : 2319 - 8648
October 2019 | SJIF | Impact Factor : 7.139

- The people who open the Jan Dhan account will now use their accounts and become familiar with banking activity. The money deposited in these accounts can be used for the development activity of the country.
- After demonetisation era 9.1 million new taxpayers were added to the slab which was an 80% rise over the typical yearly rise. This increase in the number of tax paying citizens in the country has been credited to demonetization.

Negative impact of demonetisation

- The very next day of announcing the demonetisation the BSE sensex and nifty 50 stock indices fellover 6%. The severe cash shortages brought detrimental impact on the economy. People trying to exchange their bank notes hard to stand in the lengthy queues causing many deaths due to inconvenience and rush.
- The sudden announcement had made adverse impact of business and economy. Instead of a growing economy India has become a stand still and no growth economy. It is feared that the fall of 2-3% in GDP growth will be recorded coming year.
- The poor planning of the part of the government has also added to the woves of the common people with low incomes. The Rs. 2000/- currency note does not have find many takers as it is difficult to get the balance back when you are buying daily needs like wheat, rice, vegetables, milk bread or paying for petly expenses like bus fair, while Rs. 100/- currency notes were not available in sufficient number.
- India is an agriculture based economy. Due to the cash crunch, the farmers especially small and marginal who largely depend on cash to buy seeds, fertilizers and to pay for sowing, borrowing water for irrigation and for other related agriculture equipments remained worst affected and could not complete the crop related activity.
- since small branches of the banks were also not supplied with adequate cash within time of sowing season of the crop. Farmers could not get their crop loans disbursed. This added to the woves of the farmer leading to a weak agriculture production the coming year.
- Real estate sector came to a standstill and it is still gasping for buyers of the constructed, and half constructed inventory without buyers. This has resulted in poor cash flow leading to a poor demand.
- Due to the inability to pay cash to poor daily wages workers the small employers have stopped their business activity.
- Demonetisation has made the situation become chaotic tempers are running high among the message as there is a delay in the circulation of new currency

Conclusion :

Export think that even from the point of view of promoting digital money, there was no need for the government to have put 86% of all currency out of circulation. Studied have pointed out that very little black money was caught on August 30, 2017. The Reserve Bank of India released its report on demonetization. The report said 99% of the banned notes to came back into the banking system. This belies the government claims that the demonetisation would flush out the black and counterfeit currency. It was not only a "morally" and "ethically" correct step but also "politically" correct.

Reference :

- Economic survey of India 2017-18
- Economic and political weekly March 2018
- Yojana 2018
- Indian economy – R. D. Sundaram

Impact Factor – 6.625 ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

International Multidisciplinary E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

February - 2020 Special Issue – 224 (E)

RELEVANCE OF GANDHIAN THOUGHTS

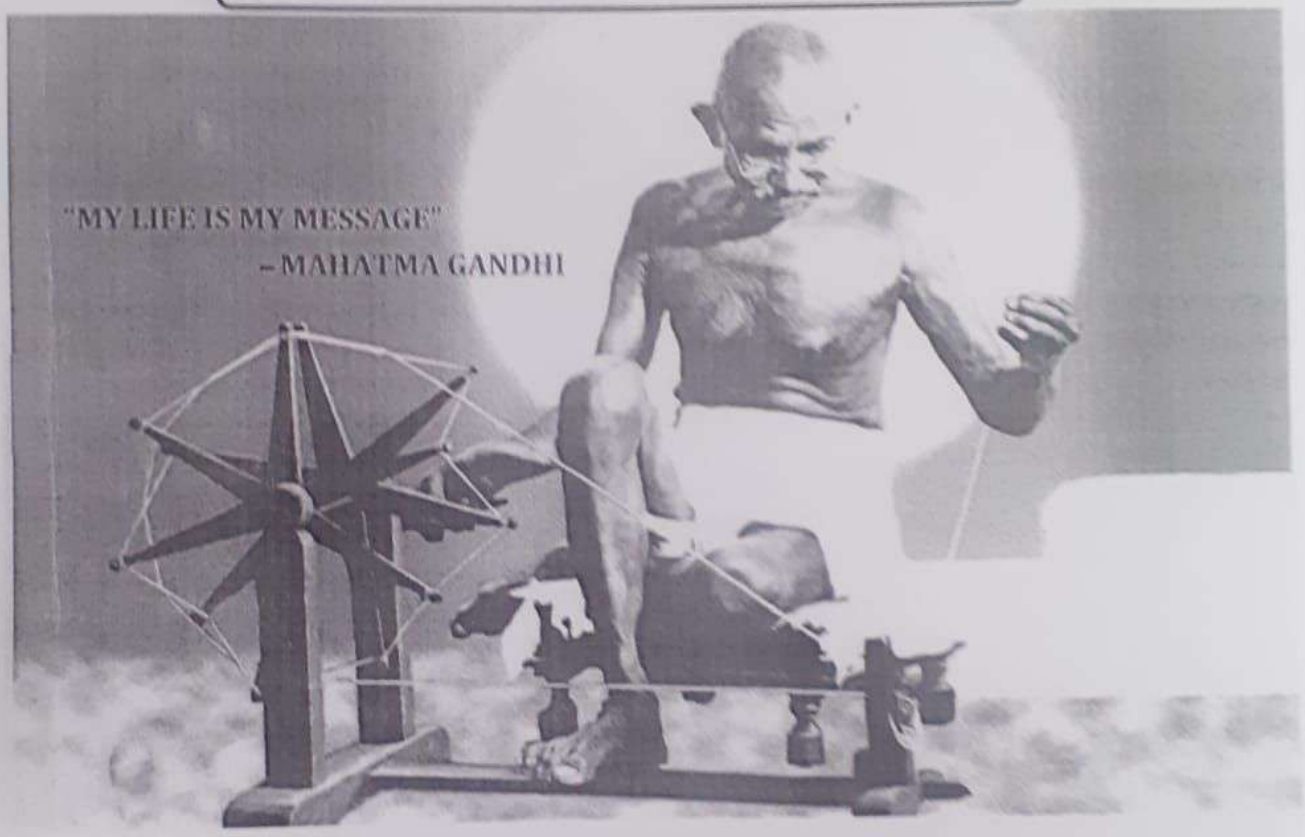

Guest Editor :
Dr. Mrs. M. V. Waykole
Principal,
Bhusawal Arts, Science and P.O. Nahata Commerce College, Bhusawal, Dist Jalgaon.

Executive Editor :
Dr. A. D. Goswami
Vice Principal,
Bhusawal Arts, Science and P.O. Nahata Commerce College, Bhusawal, Dist Jalgaon.

Chief Editor :
Dr. Dhanraj
(Yeola)

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION

Peer Reviewed Journal

ISSN 2319-8648

Impact Factor (SJIF)

Impact Factor - 7.139

Current Global Reviewer

International Peer Reviewed Refereed Research Journal Registered & Recognized
Higher Education For All Subjects & All Languages

Special Issue 21 Vol. II
on

Recent Economics Policies and Its Impact on Indian Economy

October 2019

Chief Editor
Mr. Arun B. Godam

Associate Editor
Dr. Mahadev Gavhane

Guest Editor
Dr. A. J. Raju

Assistant Editor
Dr. P. G. Kawale
Dr.P. R. Rodiya
Dr. S. J. Kulkarni
Dr. V. D. Dhumal

www.publishjournal.co.in

CURRENT GLOBAL REVIEWER
Special Issue 21, Vol. II | Peer Reviewed | ISSN : 2319 - 8648
October 2019 | SJIF | Impact Factor : 7.139

Demonetisation and its impact on Indian Economy

Prof. Dr. Ramesh P. Joshi
HOD and Associate , Professor in Economics , Shri Sant Gadge Baba Hindi Mahavidyalaya Bhusawal Dist. Jalgaon

Abstract :

The demonetisation was announced as a surprise in the night on November 8 2016. The economic survey of India was released just before the presentation on general budget 2018 in parliament emphasized that all the negative impact of demonetisation of Rs. 500/- and Rs. 1000/- currency note has ended. However the analysis in India and abroad has claimed that demonetisation of November 2016 has failed to do what it was supposed to do and its impact has turned out to be more pretracted then initially expected.

Keywords :
Growth, demonetization, economic, digital, currency, cashless, GDP etc.

Introduction -

While the year 2019 will bring with it formation of new government after the election in April 2019 the after effects of demonetisation that happened on November 8, 2016 steel haunt Indian economy. The demonetisation was announced as a surprise in the night of November 8, 2016. The Indian prime Minister announced his plan of banning Rs. 500/- and Rs. 1000/- notes with several motives in mind and thus began and thus begin Indians struggle with demonetization. A year after the country was wiped out of old currency, the impact of Narendra Modi's demonetisation can still be felt in the economy. Demonetisation was initiated with a wide array of motives like stripping the Indian economy of its black money, push people to pay taxes for the unaccounted pile of cash, curb terrorism, promote the digital India movement and make India a cashless economy.

Demonetisation positive impact on Indian economy.

Economic survey after careful review of demonetisation which was announced and a half year back, has found that the cash to GDP ratio has stabilize. It suggest a return to equilibrium .

- The economic survey says that India's GDP is set to grow at 7 to 7.5% in 2018-19 this is an increase from its prediction of 6.75 percent growth this fiscal year.
- The economic survey has cited export and import data to claim that the demonetisation effect was now over. It claims that reacceleration of export growth to 13.6% in the third quarter of financial year 2018 and declaration of import growth to 13.1 percent is in line with global trends. This suggest that the demonetisation and GST effect are receding services, export and private remittances are also rebounding.
- The unaccounted cash could be deposited in the Pradhan Mantri, Garib Kalyan Yojana after paying 50% tax. The money will remain deposited for 4 years. With the bank without incurring and interest However after 4 years the amount will be returned. This amount can be utilized for social welfare schemes and making the life of low income group better.
- According to the statistics released in the survey the demonetisation had led to Rs. 2.8 lakh crore less cash (equivalent to 1. 8% of GDP) and rs 3.8 lakh crores less high demonetisation notes (equivalent to 2.5 % of GDP) in the Indian economy.
- The public sector banks which where reling under deposit crunch and were running short of funds have suddenly is welled with lot of money which can be used for future finance and loans after keeping a certain amount of reserve as per RBI guidelines.
- One of the biggest achievement of demonetisation has been in the drastic curb of terrorist activities as it has stopped the funding the terrorism which used to get a boost due to inflow of unaccounted cash and fake currency in large volume.

Nagpur University Nagpur)
Shivaji Nagar, Bhusawal (02582) 225238

'RESEARCH JOURNEY' International E- Research Journal | E-ISSN : 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013) | Vol. 6, Issue 2 | April-May-June 2019
UGC Approved Journal | 2019

बुनियादी ढांचे का निर्माण–

सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों की एक दिक्कत बुनियादी ढांचे का अभाव है। एक दुर्गम क्षेत्र में छोटे उद्योग से शुरू करना तथा चलाना लगभग असभव होता है। रेल, सड़क, बैंकिंग सुविधा, पानी, दूरसंचार आदि सुविधाओं के अभाव के कारण ऐसे उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा खास तौर पर ग्रामीण इलाको में ई–प्रोक्योरमेंट योजना का प्रारंभ किया गया है। ताकि अनुकूल वातावरण बन सके। हमें रेल, सड़क, बिजली, कौशल विकास, बाजार जैसी बुनियादी ढांचे को विकसित करने की जरूरत है।

भारी आयात एवं डंपिंग पर प्रतिबंध–

सामान्यतया विदेशी व्यापार, लघु उद्योगों के लिए संकट का बायस है। इसका कारण कुछ विदेशी देशों, विशेष रूप से चीन द्वारा की जाने वाली डंपिग है। परंतु अब केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया गया है। अब चीन से आयात के किए गए ९३ उत्पादों पर एंटी डंपिग शुल्क लागू है । वर्ष २०१६–१७ में कुछ वस्तुओं पर एंटी डंपिग शुल्क लगाने के परिणाम मिल चुके हैं । इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि चीन से आयात में गिरावट होगी। इससे घरेलू लघु उद्योगों को राहत मिलेगी।

सरकारी खरीद में वरीयता–

लघु उद्योगों को संरक्षण तथा बढावा देने के उद्देश्य से ऐसी व्यापक और स्पष्ट सरकारी की नीति थी कि एसएसआई से खरीद को वरीयता दी जाएगी। वर्तमान सरकार द्वारा जनरल फाइनेंशियल नियम बनाकर (जीएफआर) बनकर एक नई खरीद नीति लागू की है । इस नियम के तहत ५० लाख से कम मूल्य के माल की खरीदी में केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही पात्र होंगे। इस तरह की वरीयता देने घरेलू उद्योग को सामान्य रूप में प्रोत्साहन मिले।

इंस्पेक्टर राज की समाप्ति–

एसएसआई पर ५० से ज्यादा निरीक्षक और ४० से अधिक कानून लागू है। बार–बार एसएसआई को दंडित करने के व्यापक प्रावधान है। इन खतरों के कारण लघु उद्योगों को उत्पादन वितरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन में बाधाएँ आती है। अतः ऐसे कुछ बेनामी कानूनों को निरस्त करने का काम शुरू किया है। अब तक १२०० से कानून रद्द किए गए और १८२४ कानूनों को निरस्त करने का प्रयास शुरू है। उद्योगों को सभी प्रकार की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।

अन्य उपाय –

लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने विगत ३ वर्षों में अनेक कदम उठाए है, जो रोजगार सृजन को आवश्यक प्रोत्साहन देगें। राजमार्ग का निर्माण, ग्रामीण सड़क विकास में तेजी, अगले पाँच वर्षों में ८.५ लाख करोड रुपए का पूंजीगत व्यय, मेट्रो रेल परियोजनाएँ आदि से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में १००% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा होगे। किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा। मुद्रा योजना से कई करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। बेहतर बुनियादी संरचना के कारण देश में अनेक औद्योगिक गलियारें बने है। 'स्टार्ट–अप' शब्द कहीं ना कहीं लघु उद्योग का प्रारूप ही दिखता है।

निष्कर्ष –

हमारे भारतीय लोग स्वभाव से उद्यमी, मेहनती और उत्साही है। उन्हें उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है । यह प्रमुख रूप में सरकार का काम है । सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जा चुका है और अभी बहुत अधिक उम्मीद है। यदि भारत को अगले दशक में ८–१० प्रतिशत विकास को बनाए रखना है, तो उसे मजबूत एवं विविधीकरण से संपन्न एमएसएमई सेक्टर की आवश्यकता होगी। इस सेक्टर ने पिछले ५ वर्षो में औसतन १८ प्रतिशत विकास दर दर्शाया है। भारतीय एमएसमएई में वैश्विक उपक्रम बनाने का सामर्थ्य है। कुल मिलाकर भारतीय लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ नवीनतम और उद्यमशीलता के जरिए नीतिगत हस्तक्षेप, व्यापार–अनुकूल परिवेश कायम करने में गतिशील भूमिका निभाने में अग्रणी होगें।

संदर्भ

१. भारत के भारत में एमएसएमई की समस्याएँ– रिसर्च गेट पब्लिकेशन १० मई २०१६
२. सूक्ष्म और लघु, मध्यम तथा उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट २०१६–२०१७
३. योजना नवंबर २०१७–१८

RESEARCH JOURNEY

"RESEARCH JOURNEY" International E- Research Journal | E-ISSN : 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013) | April-May-J
Vol. 6, Issue 2 | 2019
UGC Approved Journal

लघु और कुटीर उद्योगों की स्थिति में सुधार

प्रा.डॉ. रमेश प्र. जोशी
असोसिएट प्रोफेसर एव विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
श्री संत गाडगेबाबा हिन्दी
महाविद्यालय, भुसावल, जिला. जलगाँव

सारांश:–

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे अकुशल, अर्ध कुशल तथा कुशल व्यक्तियों को रोजगार पैदा करते है तथा इनकी पूंजी लागत की लागत भी बहुत कम होती है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह श्रम –केंद्रित होती है । सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) यह लघू एवं कुटीर उद्योगों का क्षेत्र है। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार लघु एवं कुटीर उद्योग है। इनमें उत्पादित कई उत्पादन देश की जरूरत के साथ–साथ निर्यात की बहुत संभावनाएँ अधिक होती है और विदेशी मुद्रा में आय प्राप्त होती है। भारत में लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा १२ करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया हैं। देश की जीडीपी में भी १७ प्रतिशत का योगदान करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

कीवर्ड :– एमएसएमई, आर्थिक विकास, विदेशी मुद्रा, निर्यात, मिलियन, उद्यशीलता आदि।

प्रस्तावना :–

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं में अपने लघू तथा कुटीर उद्योगों के जरिए एक विशेष स्थान है। भारत की अर्थव्यवस्था में इन एमएसएमई का काफी सार्थक योगदान रहा है । साल २०१५–२०१६ में इस क्षेत्र से जुड़े ५१ मिलियन उद्योगों ने लगभग ११७ मिलीयन रोजगार दिया और इनसे जुड़े राशि ८४९२ मिलीयन रूपये तक पहुंची है। सन २०१४–१५ में एम एस एम ई सकल घरेलू उत्पादन में ३०.७४ प्रतिशत की भागीदारी रही है। एमएसएमई का जीडीपी मे ८ प्रतिशत योगदान रहा है । विनिमय उत्पादन में ४५ प्रतिशत और निर्यात ४० प्रतिशत हिस्सा रहा है। इससे भारत की सहभागिता सराहनीय प्रयास है, क्योंकि इसमें उद्यमियों के लिए बहुत सी योजनाएँ जनजातियों, हाशियाकृत समुदायों और दिव्यांग लोगों को साथ जोड़कर उन्हें उद्यम के सृजन के योग्य बनाया जाता है।

एम एस एम ई क्षेत्र की अंतर्निहित क्षमता के बावजूद अनेक समस्याएँ मौजूद है। जिसमें समय पे ऋण न मिलना बुनियादी के ढाँचे की कमी, परंपरागत तकनीक, बाजार तक पहूँच न होगा, तथा कुशल श्रमिकों का अभाव होना, प्रतियोगिता आदि शामिल है। पिछले कुछ वर्षो में इस क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए कई उपाय किए गए है। उनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार के है।

वित्तपोषण–

भारत में एमएसएमई का क्षेत्र एक समान नहीं है। इसलिए उनकी प्राथमिकताएँ अलग–अलग है। जिसमें आर्थिक सहायता न मिलना प्रमुख प्रमुख हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों को समय पर तथा पर्याप्त ऋण मिलना जरूरी है । मध्यम तथा बड़े उद्योगों के लिए यह इतनी बड़ी समस्या नही है। सूक्ष्म तथा लघु उद्योगो के लिए यह बड़ी चुनौती होती है। नये सुधारो के तहत अब यह ईकाइयाँ चुनिंदा संस्थानों से १करोड रुपए के स्थान पर २ करोड रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन ले सकते हैं। इसके अलावा बाजार में नए मॉडल भी

आए है। कार्यशील पूँजीगत क्षेत्र में विभिन्न स्टार्ट–अप ऐसा प्रयास कर रहे है। एसएसएमई ऋण गारंटी न्यास का गठन कर एमएसई को ऋण देने का प्रावधान है।

मार्केटिंग सहयोग योजना (एमएएस)–

इस योजना के तहेत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों , विक्रेताओं–खरीददारों क बैठकों, अभिव्यंजनो / संगोष्ठियों में प्रतियोगिता हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों की सहायता की जाती है। इसका कार्यान्वयन एसएमई मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किया जाता है । नई बुलंदियों को छूने की दिशा में यह एक सशक्त कदम है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जिससे एसएमई की मार्केटिंग एव प्रतियोगिता क्षमता बढ़ेगी और नया एक्सपोजर मिलेगा।

निर्यात हेतु ई–वॉलेट स्कीम–

निर्यातकों की रिफंड में फाँसी से राशि को ध्यान में रखकर जीएसटी काउंसिल ने विशेष तौर पर ई–वॉलेट स्कीम का प्रारंभ किया है । एक अनुमान है कि भारतीय निर्यातकों के लगभग ६५,००० करोड़ रुपए फँसे हुए है। इस नई योजना को लॉन्च करने से निर्यातकों को ई–वॉलेट में अभासी अग्रिम भुगतान दिया जाएगा। जिसे बाद में उन्हें मिलने वाले टैक्स रिफंड से निकाल लिया जाएगा।

रिटर्न भरने की प्रक्रिया में सरलीकरण –

छोटे कारोबारियों की एक प्रमुख समस्या जीएसटी में रिटर्न भरने की बारंबारिता थी। जीएसटी के तहत कारोबारियों हर महीने रिटर्न भरना पड़ता था। जो एक बड़ा सिर दर्द रहता था। अब जीएसटी काउंसिल ने १.५ करोड रूपये तक के टर्न ओवरवाली इकाईयों को अब तिमाही रिटर्न भरने की छूट दे दी है। यह छोटे कारबारियों के लिए बडी राहत है। इसके साथ ही रिफंड की राशि को भी १० अक्टूबर तक वापस कर दिया जाएगा। यह एक बड़ी राहत है।

टैक्स स्लैब में सुधार–

जीएसटी काऊंसिल ने कई उत्पादों के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है। बिना ब्रांडवाली नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएँ, आम पापड, खाकरा आदि को १२ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत टैक्स स्लैब में परिवर्तित किया है। टेक्सटाईल क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली मानव निर्मित सूत को १८ से कम करके १२ प्रतिशत जीएसटी स्लैब में डाल दिया है । इससे कारोबार में तेजी लाने की दृष्टि से यह एमएसएमई के लिए अच्छा प्रभाव डालने का फैसला होगा।

खादी और ग्रामोंद्योग प्रशिक्षण केंद्र –

खादी तथा ग्रामोंद्योग यह देश की बड़ी विरासत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है । ग्राम उद्योग मंत्रालय की ऐसी अनेक योजनाओं को जो ग्रामीण बेरोजगारों को विशेष रूप से युवाओं तथा महिलाओं को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रशिक्षण भी देती है। जिसमें बुनाई, कताई, ईडीपी, मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यह ग्रामीणों के रोजगार की अच्छी पहल है।

- Supermarkets will establish there monopoly in the Indian market. Because of supermarket's fine tuning, they will get goods on low price and the will sell it on low price.
- Job in the manufacturing sector will be lost because foreign giants will purchase their goods from the international market and not from domestic market and not from domestic sources.
- Draining of Money - In spite of FDI coming into the country by the company is basically deployed to earn profits from the native customers therefore the net amount earned is transferred to the parent nation.
- The price of commodities will rise higher making it difficult for middle class and low income groups to meet their needs.

Conclusion –

India has been one of the developing countries and has managed to show a positive GDP growth even during the recession period. It has comparatively performed well, them the average growth rate of world GDP. India has all the variables such as fine infrastructure , potential markets abundant labor availability of natural resources and at last the economic and trades policies which has been favoring FDI. India is now rated as the second most favoring destination for FDI in the world after china but it is expected that in future India would out bet china as it has a large proportion of young population with one of the fastest growing economies, Instead of the government should formulate the policies which can attract more foreign investment in manufacturing sector than service sector.

References

1. India current affairs -2014
2. Competition success – 2017 -2018
3. Indian economy – R.D. Sundaram

Impact Factor – 6.261 E-ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

International E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

Vol. 6, Issue 2

April-May-June 2019

Chief Editor -
Dr. Dhanraj T. Dhangar,
Assist. Prof. (Marathi)
MGV'S Arts & Commerce College,
Yeola, Dist – Nashik [M.S.] INDIA

Executive Editors :
Prof. Tejesh Beldar, Nashikroad (English)
Dr. Gajanan Wankhede, Kinwat (Hindi)
Mrs. Bharati Sonawane-Nile, Bhusawal (Marathi)
Dr. Rajay Pawar, Goa (Konkani)

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION

This Journal is indexed in :
- University Grants Commission (UGC)
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.researchjourney.net

Swatidhan Publications

FdI in India-:

The last decade at 20th century witnessed a drastic increase in foreign direct investment (FDI) accompanied by a marked change in the attitude of most developing countries towards inward investment. FDI flow have grown in importance relative to other forms has increase as a share of world output , Naturally the attitude towards Foreign capital was of fears and sufficient account of the previous bitter experience draining away of the resources from the country, once better known as the global birds.

Foreign direct investment (FDI) in India has played and important role in the development of the Indian economy during the recession. FDI in india has in a lot of ways enabled India to achieve a certain degree of financial stability , growth development This money has allowed India to fears on the areas that may have needed economic attention and address various problems that continue to challenge the country. The factors that attracted investment in India are stable economic policies a availability of cheep and quality human resources and opportunities of new unexplored markets. Mostly FDI are flowing in service sector and manufacturing sector recorded very low investments, India has been ranked at the second place in global foreign direct investment.

Importance of FDI in India –

- Capital has been one of the scare resources that are usually required for economic development. Capital is limited and there are many issues such s health , poverty, employment, education, research and development, technology, obsolesce, global competition.
- Basic economic infrastructure – In the recent years foreign financial institutions and government of advanced countries have made substantial capital available to the under developed countries. FDI help in developing infrastructure by establishing firms different part of country.
- Sustaining a high level of Investment- As all under-developed and the developing countries want to industrialize and develop themselves , therefore becomes necessary to raise the level to investment substantially . Due to poverty and low GDP the saving are low. Therefore there is need to till the gap between in come and savings through foreign direct investment.
- For Technology -In India scenario we need technical assistance from foreign source for provision if expert services, training of Indian personal and educational research and training institutions in the industry .It only comes through private foreign investment.
- Use of Natural resources-In India we have abundant natural resources such as coal, iron, steel but to extract the resources we require FDI.
- Understanding the initial risk- In developing countries as capital is a scare risk of investment in new projects for industrialization is high , therefore foreign capital help in these investments which require high risk.

Market size :-

According to department for promotion of industry & internal Trade (DPIIT) the total F.D.A. In India April – December 2018 stood of us $ 33.49 Billion.

Data for April – Dec 2018 indicates that the chemicals (other than fertilizers) sector attracted the highest FDI equity inflow of us $ 6.06billion followed by services us$ 5.92 billion

computer software hardware US $ 4.75 billion & trading us $ 2.34 billion most recently the total FDI equity inflows for the month of December 2018 touched US $ 4.39 billion.

During April – December2018 India received the maximum FDI equity inflows from Singapore (US $ 12.98 billion) followed by Mauritius (US$ 6.02 billion) Netherland (US $ 2.95 billion) USA (US $ 2.34 billion) & Japan (US $ 2.21 billion)

Benefits of FDI (advantages)

Various benefits of FDI in India are given below

1) Promotion of investment in key areas –by following FDI we can promote investment in key areas such as infrastructure development as a result of which there wil be more production of capital goods for exp :- investment in power generation can generate more electric power which will enable the growth of more industries .
2) New technologies :- FDI can bring in more new technologies which were not adopted in the country till now recent development in the communications system. The launching of satellites with the help of other countries has enabled the growth of communication system in the country. Nokia has come to India promoting India's communication system.
3) Increase in exports – with the help of FDI the exports of manse under develop contrives have increase the creation of economics zones and promotion of 100 % export orienting units have help FDI in increasing there experts from other countries. Certain consumers products produced by them have world wide markets.
4) Employment opportunities- the advent of FDI in developing countries has promoted the serice sector. This has resulted in a change in the advertising and marketing technologies. This provides more scope for employments opportunities.
5) Capital inflow- FDI promotes .mortem capital inflow into them country as special in key and core sectors. We have a shortage of capital not only in the form of money but also in the form of material.
6) Financial services- FDI strength then financial service of country by not only interring its banking industry but also expanding other activities industries such as merchant banking portfolio investment etc. which as resulted in promotion for more new companies.
7) Development of back word areas- FDI are in a way responsible for the development at back word area. There are some many industries started by them in far reaching and backsword areas has a result of which area have developed into industries countries. Hyundai & ford car units started at Sriperumbaduran an Maraimalainagar in India.
8) Change in life style – The presences of FDI has no doubt change the life style pattern of people the purchase of consumer goods as T.V. fridge automobiles are made possible as these goods are made available through hire purchase system.

Arguments against FDI –

- FDI will lead to job losses. Small retailers and other small. Kirana store owners will suffer a large loss. Giant retailer and supermarkets like Wal-Mart, Carrefour, etc will displace small retailers

'RESEARCH JOURNEY' International Multidisciplinary E- Research Journal
Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013)
Special Issue 175 : Revolutionary Changes in Trade & Foreign Capital (RCTFC2019)
UGC Approved Journal
ISSN : 2348-7143
March-2019

INDEX

No.	Title of the Paper	Author's Name	Page No.
1	भारतातील परकीय भांडवलामधील क्रांतीकारी बदल	डॉ. उमेश घोडेस्वार	05
2	भारताच्या विदेश व्यापाराच्या प्रवृत्तीचे अवलोकन	प्रो. एन. एल. चव्हाण	14
3	आर्थिक विकासात थेट विदेशी गुंतवणुकीचे योगदान	प्राचार्या डॉ. मंगला साबद्रा व डॉ. सुमित्रा पवार	19
4	जागतिकीकरण, स्वीवाद व स्त्री सक्षमीकरण	डॉ. सर्जेराव गोल्डे व प्रा. सविता जावळे	23
5	Role of Foreign Trade in Economic Development of a Country	Mrs. Sangita Dharmadhikari	28
6	Foreign Direct Investment	Dr. Ramesh Joshi	32
7	Socio-Economic Impact of Globalization in India	Dr. Vidya Patil	36
8	The Direction of India's Foreign Trade	Prof. Ibrahim Pinjari	42
9	A Study of Fiscal Position of Maharashtra under Rule Based Framework	Dr. Manojkumar Gaikwad	44
10	Foreign Direct Investment	Mr. P. P. Chaudhari	48
11	Impact of Globalization on Indian Economy	Dr. Ravi Kesur	50
12	Foreign Trade Policy in India	Dr. Mamataben Patil	56
13	Role of Foreign Capital in Indian Economy	Dr. Rajkuvar Gajare	60
14	Recent Trend of Indian Consumer's Behaviour	Prof. Baisane Pandit	66
15	Recent Trends in Foreign Trade	Miss. Dixita Salunke	69

Our Editors have reviewed paper with experts' committee, and they have checked the papers on their level best to stop furtive literature. Except it, the respective authors of the papers are responsible for originality of the papers and intensive thoughts in the papers. Nobody can republish these papers without pre-permission of the publisher.

- Chief & Executive Editor

'RESEARCH JOURNEY' International Multidisciplinary E- Research Journal
Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013)
Special Issue 175 : Revolutionary Changes in Trade & Foreign Capital (RCTFC2019)
UGC Approved Journal
ISSN : 2348-7143
March-2019

(5)

Foreign Direct Investment

Prof. Dr. Ramesh Prabhakar Joshi
Head of the Department of Economics
Shri Sant Gadgebaba Hindi Mahavidyalaya, Shivaji Nagar, Bhusawal

Abstract :-

Foreign Direct Investment is a major source of non-debt financial resource for the economic development of India. It is economic driver of economic growth. Foreign companies in invest in India to take advantage of relatively lower wages, special investment privilege such as tax exemptions etc. For a country where foreign investment are being made, it also means achieving technical know-how and generation employment.

The Indian government's favorable policy regime and robust business environment have ensured that foreign capital keeps flowing into the country. The Government has taken many initiatives in recent years such as relaxing FDI norms across sector such as defense PSV, Oil refineries, Telecom, Power Exchanger and stock exchanges, among others.

According to Department for promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) the total Foreign Direct Investment in India. April-December 2018 stood as US $ 33.49 billion, indicating that Government's effort to improve ease of doing business and relaxation in FDI norms is yielding result.

Key Words : Foreign, Investment, Exchange, Financial, Development, Employment.

Introduction :-

Foreign direct investment is one of measure of growing economics globalization .Investment has always been an issue for the developing economics such as Indian. The world has been globalized & all the countries are liberalizing their policies for welcoming investment from countries which are abundant in capital resources. The countries which are developed are focusing on new markets where there is availability of abundant labors ,scope for products and high profits are achieved. Therefore foreign direct Investment (F.D.I.) has become a battle ground in the emerging market . The objective behind allowing FDI is to complement and supplement domestic investment for achieving a higher level of economic up-gradation, as well as access to global managerial skill and practices.

South Asian countries such as china have implemented open door policies during 1980's but India liberalized conservative policies to protect the indigenous investors and industrials. The economic growth has not been achieved In 1991 the then congress Government had implemented liberalization policies to restructure the India economy.

Objectives of Study

-To understand the importance for FDI in India

-To understand the benefit of FDI

RESEARCH METHODOGY –:

The secondary data was collected from various journals, magazines, reference books and websites.

International Multidisciplinary E- Research Journal
Impact Factor - (SJIF) - 6.261
Special Issue 122A : Implementation and Impacts of Goods & Service Tax (GST) on Indian Economy
ISSN : 2348-7143
Feb. 2019

Impact and challenges of GST in India

Dr. Ravi Nandlal Kesur
Assistant Professor, Dept of Commere, Dhanaji Nana Mahavidyalaya, Faizpur

Abstract:
GST or Goods and Services Tax, the best assessment change in India since autonomy which has been long pending. GST is intended to improve the backhanded expense routine of India by supplanting a large group of assessments by a solitary bound together duty. GST is the main aberrant expense that specifically associates all the division of Indian economy subsequently improving the financial development of the nation by making a solitary brought together market. In excess of 160 nations of the world have actualized GST so far pursued by France. The possibility of GST in India was proposed by Atal Bihari Vajpayee in 1999 and a council was set up under the administration of Asim Das Gupta the then back priest of West Bengal. It should be actualized from first April 2010 under lead of P Chidambaram the then back clergyman of UPA government however because of political issues and clashing interests of different partners it didn't came into power. In May 2016 the protected alteration bill for GST was passed by LokSabha and due date of first April 2017 to execute GST was set by ArunJaitley the back clergyman of India. Be that as it may, there is a colossal objection against its usage. This paper exhibits an outline of GST idea, focal points and clarifies its highlights alongside centered in difficulties looked by India in execution.

Keywords: Goods and services Tax, Challenges and Issues , Impact of GST, Indian economy

Introduction

Products and administration impose is one backhanded assessment for the whole country, to make India one brought together basic market. It is a multi organized, goal put together assessment collected with respect to each esteem expansion. It was started by the UPA government and was put into power by Narendra Modi government. GST has supplanted the circuitous assessment system.The Goods and Services Tax was propelled at midnight on 1 July 2017 by the President of India, Pranab Mukherjee, and Prime Minister of India, Narendra Modi. The Members of DMK and different gatherings too. The gatherings detailed that there was no distinction between the then existing expense framework and GST. They likewise contended that the GST would increment existing rates on the basic every day merchandise while lessening the rates on the extravagances, and influence the white collar class society unfavorably to the greatest degree henceforth expanding the rich poor hole.

The past expense framework included

- Direct expense: - salary duty and riches impose.
- Indirect duty: - focal government collect focal extract, traditions, benefit assess; state government exact VAT, excitement charge, extravagance duty and passage assess.

The GST expects to handle a significant number of the issues of the past framework by joining the focal and state roundabout assessments, and present two combined charges State Goods and Service Tax (SGST) and Central Goods and Service Tax (CGST) and furthermore Integrated Goods and Service Tax (IGST). Under the new expense framework, the exchanges will have a demand of both SGST and CGST upon them with settled piece rates relying on the merchandise or administrations.

Objective of Study

1. To Understand the concept of GST
2. To study Benifits of GST
3. To Study the Impact and challenges of GST

Research Methodology

An illustrative research is considered dependent on auxiliary information gathered from different diaries, books, government reports, articles and papers which center around various parts of Goods and Services Tax.

Benefits of GST

1. It would introduce "one country one tax"
2. It would absorb all the indirect taxes at the central and state level thus eliminating the cascading effect of tax
3. It would bring down the prices of goods and services which in turn will help the companies as consumption will increase
4. Higher threshold for registration which will exempts many small traders and service providers.
5. In the GST system, when all the taxes are integrated it would eliminate the number of compliances like return filling
6. It would help to eliminate the separate tax imposition on goods and services which requires the transaction to split its value among goods and services leading to greater complications
7. It would wider the tax regime by covering all the sectors including the unorganized sectors thus widening the tax base. This would lead to better and more revenue collection by the government.
8. GST would simplify the working procedures and would minimize the tax burden of E-commerce and logistics companies
9. Employment generation for youths as GST trained experts

Impact of GST

'RESEARCH JOURNEY' International Multidisciplinary E- Research Journal | ISSN : 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) - 6.261 | Feb. 2019
Special Issue 122A : Implementation and Impacts of Goods & Service Tax (GST) on Indian Economy

Impact of GST on Indian Economy

Prof. Dr. Ramesh P. Joshi
Associate professor, H.O.D of Economics/Shri Sant Gadge Baba Hindi Mahavidyalaya, Shivaji nagar, Bhusawal.

Abstract :-
The introduction of the goods and services tax (GST) will be a very noteworthy step in the field of indirect tax reforms in India. By merging a large number of central and state taxes into a single tax. GST is expected to significantly ease double taxation and make taxation overall easy for the industries and traders. Its also beneficial for the end consumer. GST holds great promise in terms of sustaining growth for the Indian economy.

Keywords:-
GST in India, impact of GST, cascading effects, sustaining growth, taxation, reforms, subsumed, expansion.

Objectives of study:-
Study has following objectives.

- To study the advantage and disadvantage of GST.
- To study the concept of GST.
- To study cascading effects on production in Indian economy.

Methodology:-
The present research paper is a study of "Impact of GST on Indian Economy" based on secondary data collected from the published report, research paper, reference books and individuals in India. Specifically the secondary sources include journals and websites.

Introduction:-
It goes without saying that the biggest and the most fare aching structural reform that the Modi government has ushered in has been the introduction and implementation of Goods and Services Tax (GST) GST has completely altered the indirect tax regime in India for all the times to come.

It has been nearly one and half year since the new tax regime come into existence at midnight on June 30- July 1, 2017, as GST. One nation, one tax, in order to simplify the taxation on goods and services. Administered by both the centre and the states, GST has sub summed several state and central indirect taxes such as state VAT, central excise Duty, Purchase tax and Entry tax. Tension of Tax payers to follow 17 various laws has been reduced and now there is only one law. There is only one tax due to which prices of various commodities have become stable.

The GST rollout with a single stroke, has converted India into a unified market of 1.3 billion citizens. Fundamentally the $ 2.4 trillion economy is attempting to transform itself by doing away with the internal tariff barriers and subsuming center, state and local taxes into a unified GST.

Impact of GST on Indian Economy:-

- Reduce tax burden on producers and foster growth through more production. This double taxation prevents manufacturers from producing to their optimum capacity and retards growth. GST would take care of this problem by providing tax credit to the manufacturer.
- There will be more transparency in the system as the customers would know exactly how much taxes they are being charged and on what base.
- Various tax barriers such as check post and toll plazas lead to a lot of wastage for perishable items being transported, a loss that translated into major casts through higher need of buffer stocks and eliminate this roadblock for them. In the US the trucks travel at least 800km a day as compared to the Indian trucks, who travel only 280km. a day. So, the logistic costs will reduce.
- Form the view point of the consumer, they would now have pay less tax for most of the Goods and Services they consume. Almost a year after the rollout of the new unified tax regime, many consumers say their monthly grocery bills have come down. While some consumers say cost of services have gone up. Government reduced tax rates on wide range of daily use appliances and product from 28% to 18% on sanitary pads, GST is zero.
- Increase Revenue collection. The evasion of tax will decrease and the input tax credit will encourage the suppliers to pay their fair share of taxes, Due to GST bill, the number of tax exempt goods will decline and also the centre and state will have oversight over the payment and collection of taxes. Revenue from the taxes for the Govt. is very likely to increase with an extended tax net and the fiscal deficit is expected to remain under the checks. Post GST 50% increase in number of indirect taxpayers and GST revenue crossed the psychological barrier of Rs. 1 lakh-crore in October 2018, coming in at Rs. 1,00,710 crore.
- There are many goods that are still outside the GST net, which comes in the way of seamless flow of input tax credit. Key times outside its ambit are electricity, alcohol, petroleum goods and real estate. Among fuel it may be possible to bring natural gas and aviation fuel within GST.
- Registration under old Indirect tax regime 6.4 million is increased under GST up to 11.2 million. It means tax base has expanded with GST. Large increase in Voluntary registrations under GST.
- More people filing tax returns under GST. In financial year 2017, 5.43 crore people were filed tax returns but in financial year 2018, 6.48 crore people filing tax returns. Reduction in procedural complexity in paying taxes, less paperwork. There has been a fifty percent increase in number of Indirect tax payers.
- Expected to increase export by more than 10% add to GDP growth India's largest firms account for much smaller

'RESEARCH JOURNEY' International Multidisciplinary E- Research Journal | ISSN : 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) - 6.261
Special Issue 122A : Implementation and Impacts of Goods & Service Tax (GST) on Indian Economy | Feb. 2019

share of export than in other comparable countries.

- Boost to the Indian economy in the long run these are possible only if the actual benefit of GST is passed on to the final consumer. There are other factors, such as seller 's profit that determines the final price of goods. GST alone does not determine the final price of goods.
- Present GST discussions indicate that cascading may continual with respect to petroleum product the serve as inputs to that extent the burden on artificial silk and synthetic fibers will continue since much of these products. Are exported, this advantage may continue unless a suitable mechanism is found to rebate input tax on petroleum products.
- Productivity enhancing effects, improvement in allocative efficiency, and modernization of textile sector encouraged.
- GST brings development in the underdeveloped states. Interaction with tax officers has reduced glitches in GST due to online portal, which must lead to reduction in corruption.
- Foreign Direct Investment (FDI) would also increases. The Industry leaders believe that the country would climb several ladders in the ease doing business with GST.
- A single taxation on production would also translate into a lower final selling price for consumer.
- The GST has gone on to create a positive sentiment among the foreign investors or buyers. After the uniform tax India's image abroad has taken a big boost because earlier the foreign investors were required to pay different tax and complete various hectic formalities. However after the arrival of the GST, now they are required to pay a single tax and have lead to an increase the foreign in investment in the Indian stock market.
- After coming up of the GST, more emphasis is devoted maintaining the digital records of the investment undertaken in the stock market. Now smaller firms that carry out the large percentage of their business in cash will now be required to maintain the digital records. One of the biggest advantage of this will be the companies will not be able to hide or under report revenues. Recently the securities and Exchange Board of India (SEBI) has made it compulsory for the dematerialization of the share held in the physical Form to April 1 2019.This will go on the minimize the fraud and manipulation risk in physical transfer to shares.
- Improvement in the Economy: With the introduction of the GST. Now there is a unified market, when we talk about the tax implementation in India. The transaction of goods and services will be quite smooth across the states. This means that there will be an improved competitiveness for the trade. It leads to the higher or excellent productivity gains and most importantly improvement in the GDP will helps in ease of doing business and make Indian economy attractive as a foreign investment destination.
- Reduce production cost – GST is expected to reduced the production cost by 15% to 20% in many of product in view of full input credit which will have favorable impact on the prices of product.
- Impact of GST on macroeconomic indicators is likely to be very positive in the medium term.

Adverse effects of GST

- GST would negatively impact the real a stock market as it would add up to 8% to the cost of new homes and reduce demand by about 12% and production process likely to take sometime to align with the new framework as firms adjust to the input tax credit system and better manage working capital requirement.
- Negative effect on working capital. As the firms are supposed to make the payment of the tax on every transfer the companies working capital requirement will shoots up by proportional to the purchase of inputs for the addition.
- The implementation of GST increased the unemployment rate (3.39 to 6.06) during July -2017 to February -2018 in India. It means negative impact of GST in rampant on employment rate.
- GST is an indirect tax that is finally recovered from consumers of goods and services in the form of increase in sale price. Thus every consumer be rich or poor pays same amount of GST for one unit of any product or services maximum population is of the middle class and or they depend on agriculture for their living. It has negative impact on common man in India.
- Some consumers say cost of services have gone up, their monthly grocery bills have increased.
- There is no good technology support for registration, return filling, tax payments IGST settlement etc.
- There is no more transparency in the system. The consumers will know exactly how much taxes they are being charged and on what base.

Conclusion :-

Goods and service Tax (GST) would be to eliminate the cascading effects of taxes on production and distribution cost of goods and service. The avoidance of cascading effects i.e. tax on tax will significantly improve to competitiveness of original goods and services in market which leads to beneficial impact to the GDP growth of the country and push to "Make in India".

Reference

1. How GST will impact Sector's – economic times.
2. GST impact on economy – Hindustan times.com
3. Competition success review – December 2018
4. Competition success review – October 2018
5. Indian economic surrey – 2018
6. GST India- Economy and Policy.
7. A Dash (2017) Impact of GST on Indian Economy.

SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINART STUDIES, SJIF 2016 – 6.177 ISSN: 2349-4766 (P), 2278-8808 (E)

अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रादेशिक असन्तुलन यह देश की पुरानी एवं व्यापक समस्या है। इसे हल करने के लिए संतुलित विकास की व्यूह रचना के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम आवश्यक है। उदारीकरण एवं निजीकरण की नीतियों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि प्रोत्साहन एवं प्रलोभन के द्वारा ही निजी क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए तैयार किया जा सकता है।

आइये, सब मिलकर अभियान चलाये।
देश की असमानता को दूर भगाएँ।।

....

संदर्भ :–

1) भारतीय आर्थिक नीति – डॉ. पी. डी. माहेश्वरी, डॉ. शीलचंद्र गुप्ता
2) India Economy - Rudradatta & Sundaram
3) भारतीय अर्थव्यवस्था – रुद्रदत्त, के. पी. एम. सुन्दरम्
4) www.niti.gov.in
5) भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. सुदामा सिंह
6) भारतीय अर्थव्यवस्था – मिश्र–पुरी
7) Indian Economy - S. K. Ghosh
8) News Papers

Impact Factor – 6.261 Special Issue - 122 A Feb. 2019 ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

UGC Approved Journal

Multidisciplinary International E-research Journal

Implementation and Impacts of Goods & Service Tax (GST) on Indian Economy

Organized by

The Shendurni Secondary Education Co-op. Society's

Appasaheb R. B. Garud Arts, Commerce and Science College,

Shendurni, Tal. Jamner, Dist. Jalgaon.

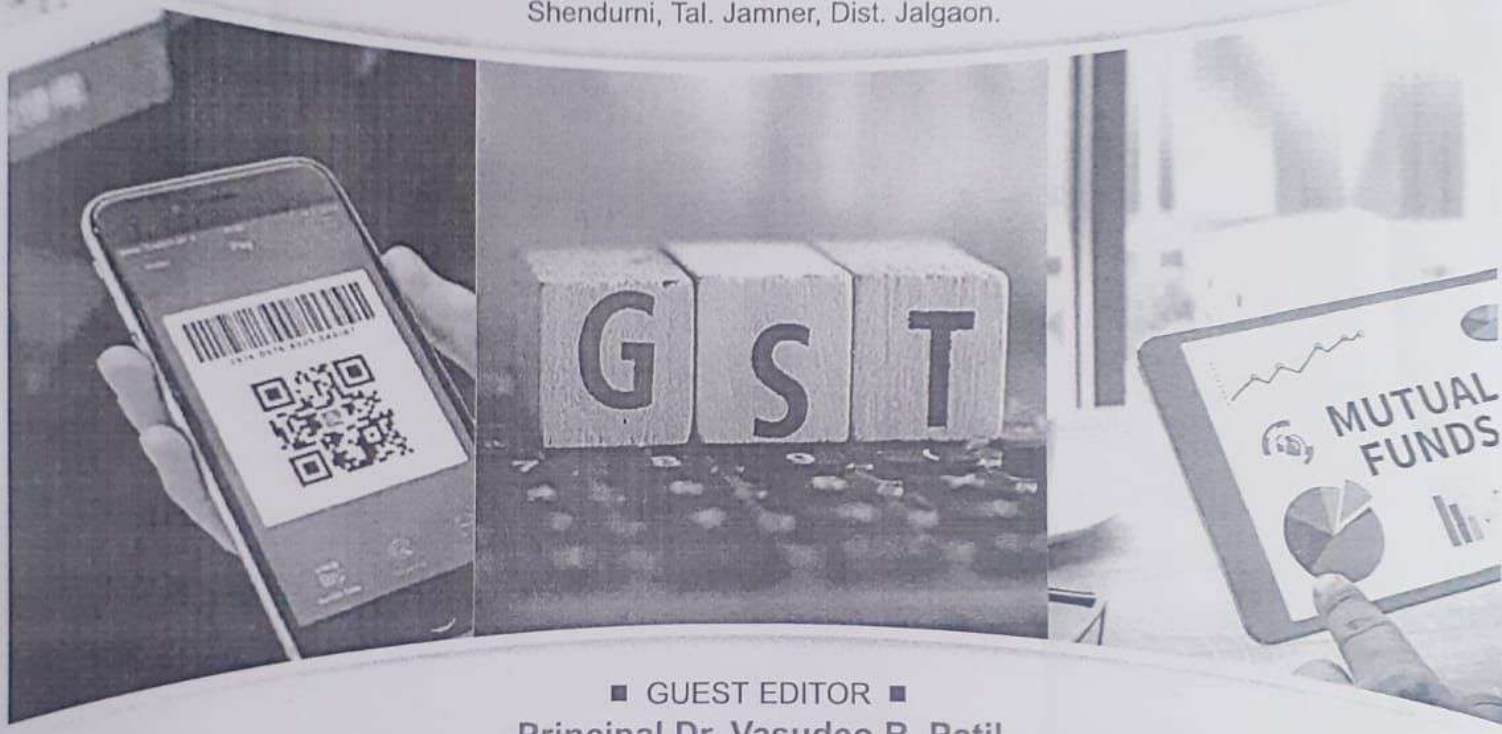

■ GUEST EDITOR ■

Principal Dr. Vasudeo R. Patil

■ EXECUTIVE EDITOR ■ **Dr. Shyam J. Salunkhe**

■ ASSOCIATE EDITOR ■ **Dr. Vasant N. Patange**

■ CHIEF EDITOR ■ **Mr. Dhanraj T. Dhangar**

RESEARCH JOURNEY

This Journal is indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- Universal Impact Factor (UIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)
- Indian Citation Index (ICI)
- Dictionary of Research Journal Index (DRJI)

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

तथा सामाजिक शांति आदि समस्याओं का उद्‌भव होने से पिछड़े हुए प्रदेशों की समस्याएँ और बढ़ती गयी है। राजनैतिक जागरण का अभाव होना यह एक प्रमुख कारण माना जाता है।

इस समस्या के समाधान हेतू निम्न कुछ प्रमुख उपायों की आवश्यकता है :–

विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना :– प्रतिव्यक्ति आय, प्रतिव्यक्ति उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, रोजगार, उद्योग आदि मापकों पर राष्ट्रीय औसत के नीचे रहनेवाले राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा प्रदान कर उन्हें विशेष मदद करने की आवश्यकता है। बिहार, झारखण्ड जैसे राज्य लगातार बाढ एवं सुखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित है। देश का 80 प्रतिशत खनिज एवं कोयले का भंडार, सोना उगलती धरती, वैभवशाली अतीत विशेष होने के बावजूद बिहार की हालात खराब है अतः ऐसे राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाना :– क्षेत्रीय असन्तुलन पर प्राथमिकता के आधार पर विशेष विचार करने की जरूरत है। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक मे वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि, बदलते वैश्विक परिवेश के अनुकूल भारत में बदलाव पर मंथन आवश्यक है। 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75 वी वर्षगाँठ होगी। इसलिए भारत की परिकल्पना साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सभी राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। सभी राज्यों को पूँजीगत व्यय और बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाने की पहल करनी चाहिए।

औद्योगिक विकास :– प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने के लिए लघु तथा मझोले उद्योग (एमएसएमई) एक बड़ा आधार है। विभिन्न प्रदेशों में मुश्किलों से जूझ रहे एम. एस. एम. ई. उपक्रमों को उबारने के लिए योजना बनानी चाहिए। देश आर्थिक विकास एवं रोजगार पैदा करने मे यह उद्योग अहम भूमिका निभाते है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों मे बिजली की समस्या गंभीर है।

कृषि विकास :– पिछड़े प्रदेशों एवं क्षेत्रों में उन्नत कृषि पध्दति के प्रचार–प्रसार एवं कृषि इनपूटस् उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता है। इन प्रदेशों में उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार करने की आवश्यकता है। स्थानीय परिस्थितियों एवं जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ाकर असन्तुलन दूर किया जा सकता है। एक ओर पंजाब तथा हरियाणा मे कृषि की उत्पादकता तेजी से बढ़ी है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उडिसा राज्यों में यह बहुत कम है। कृषि को प्रोत्साहित करनेवाली नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी, वृक्षारोपण, कृषि, पशुपालन, वानिकी आदि के विकास की आवश्यकताएँ है। कृषि मे आज भी हरितक्रांति का इंतजार है।

पिछड़े प्रदेशों में निवेश :– प्रधानमंत्री के 'सबका साथ सबका विकास' इस नारे को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है कि, उन लोगों पर ध्यान दिया जाए, जो विकास की दौड़ में पिछड़ रहे है। देश मे पिछले 25 साल की आर्थिक नीतियों में सबसे ज्यादा उपेक्षा कृषिक्षेत्र की हुई है। पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच पनपी–क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने के लिए इन प्रदेशों में निजी निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है। सरकार के पास इस समय कोष की कमी नहीं है और यह उसके ढाँचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का सही समय है। 'स्टार्ट अप इंडिया', 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया' आदि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बड़े निवेश का इंतजार है।

अन्य उपाय :– उपरोक्त उपायों के अलावा भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वयन, सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार करना, निर्धनता तथा दरिद्रता निर्मुलन कार्यक्रमों को सक्रिय क्रियान्वयन करना, मूल्य नीति तथा वितरण नीति में सुधार लोगों में जनजागृति लाना आदि का समावेश है।

NATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

March -2019 Special Issue – 175

Revolutionary Changes in Trade & Foreign Capital (RCTFC2019)

Guest Editor:
Dr. Mangala Sabdra
Principal
Smt. P. K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya,
Bhusawal, Dist. Jalgaon

Executive Editors of the issue:
Dr. R. S. Gajare, Smt. P. K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya, Bhusawal
Dr. S. C. Patil, Smt. P. K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya, Bhusawal
Dr. S. V. Pawar, Smt. P. K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya, Bhusawal
Dr. C. D. Wani, I. M. R. College, Jalgaon

Chief Editor:
Dr. Dhanraj Dhangar (Yeola)

This Journal is indexed in :

- University Grants Commission (UGC) List No.
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

– National level Seminar – Impact of GST – Paper Published
~~Kotett~~ Shendurni – International R. Journey

कर्नाटक 159971/–, हिमाचल प्रदेश 147330/–, आंध्र प्रदेश 137814/–, महाराष्ट्र 130858/–, पंजाब 126606/– रु प्रति व्यक्ति आय है तो इसकी तुलना में निम्न प्रतिव्यक्ति आयवाले राज्य मध्यप्रदेश 59052/–, उत्तर प्रदेश 54658/–, राजस्थान 70966/–, बिहार 36964/–, मिझोराम 97687/– रु है। इन आँकडों से यह स्पष्ट होता है कि, देश के कुछ गीने चूने राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय औसत से अधिक है तो कुछ राज्य औसत से कम है। प्रादेशिक असन्तुलन के यह आँकडे जीता जागता उदाहरण है।

कृषि :– चावल के प्रति हेक्टर उत्पादन में दो हजार कि. ग्रें. से अधिक आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मु एवं काश्मीर, मणिपूर, पंजाब, तामिळनाडू की हिस्सा है, तो शेष राज्यों में 1000 किलोग्राम के आसपास उत्पादन है। अन्य फसलों के उत्पादन में भी यह राज्य पिछड़े हुए है।

उद्योग :– देश में औद्योगिक दृष्टि से भी प्रादेशिक असन्तुलन पाया जाता है। यह असन्तुलन कारखानों की संख्या स्थायी पूँजी, रोजगार, उत्पादन, शुध्द आय एवं प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर देखने को मिलता है। विभिन्न राज्यों में उद्योगों की संख्या में काफी अन्तर है। 10 हजार से अधिक कारखाने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तामिळनाडू यह विकसित राज्य है। 5 हजार से 10 हजार तक संख्या वाले राज्य कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल यह है। 5 हजार से कम संख्यावाले राज्य असम, बिहार, केरळ, उडिसा, मध्य प्रदेश यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य है।

साक्षरता :–साक्षरता की दृष्टि से भी प्रादेशिक असन्तुलन है। केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं हिमाचल प्रदेश जहाँ साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश इन राज्यों में औसत से कम साक्षरता है। साक्षरता का प्रभाव आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के सामान्य जीवनस्तर पर भी पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, देश के कुछ राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित है तो कुछ राज्य पिछड़े है। उल्लेखनीय यह है कि एक राज्य के सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित नहीं है, अर्थात कुछ जिले तुलनात्मक अधिक विकसित है, वही कुछ अधिक पिछड़े है।

रेल तथा सड़के :– भारत में दक्षिण तथा पश्चिम प्रदेशों में सड़क यातायात की अधिक सुविधा है तथा रेल्वे यातायात में पूर्वी प्रदेश संपन्न है। अर्थात पिछले कुछ वर्षो में नॅशनल हायवे में काफी बढोतरी हुई है। परंतु पूर्वी तथा उत्तरी प्रदेशों में पहाड़ी इलाकों के कारण सड़कों का जाल कम है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी प्रदेशों का जिसमें तामिळनाडू तथा कर्नाटक की विकास दर अधिक है। इसी तरह से पश्चिमी राज्य गुजरात तथा गोवा की विकास दर अधिक है।

मानव विकास निर्देशांक :– देश में मानव विकास निर्देशांक के अनुसार केरल 790, दिल्ली 750, हिमाचल प्रदेश 652, गोवा 617, पंजाब 602, छत्तीसगढ़ 358, ओडिसा 362, बिहार 367, मध्य प्रदेश 375, झारखंड 376 निर्देशांक है।

भारत में प्रादेशिक असन्तुलन के कारण :–

ऐतिहासिक कारण :– भारत में प्रादेशिक असन्तुलन की शुरूआत ब्रिटीश साम्राज्य से ही हुई है। ब्रिटीश काल में तत्कालीन उद्यमियों ने अपने लाभ के लिए देश के कुछ गिने चूने प्रदेशों में ही उद्योगों का प्रारंभ किया, जहाँ प्रचूर मात्रा में कच्चा माल तथा संसाधन उपलब्ध थे। प्रारंभ में ब्रिटीश उद्यमियों ने अपना ध्यान केवल दो प्रदेशों पर ही जैसे पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र केन्द्रीत किया। इसमें भी तीन बड़े शहर जिसमें कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई ने ही उद्योगों का केन्द्रीयकरण हुआ। इन प्रदेशों की तुलना में बाकी राज्य उपेक्षित रहे। ब्रिटीशों की शोषण की नीति के फलस्वरूप देश में प्रादेशिक असन्तुलन को प्रारंभ हुआ।

भौगोलिक घटक :– देश के विकास में भौगोलिक घटकों की भी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। जो प्रदेश पहाडी है, जहाँ नदीयाँ अधिक है, घने जंगल है, ऐसे प्रदेशों में उद्योगों के विकास में काफी अडचने पैदा होती है तथा उनकी लागतें भी अधिक होती है। ऐसे प्रदेशों में साधनों में गतिशिलता कम पायी जाती है उदा. के हिमालयीन प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरी काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, उत्तरपूर्व राज्य, इनके विकास में भौगोलिक बाधाएँ अधिक है। इसलिए असन्तुलन बना हुआ है।

संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव :– किसी भी प्रदेशों के विकास में संरचनात्मक सुविधाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती जैसे यातायात, दूरसंचार की सुविधाएँ, बिजली, बैंक, बीमा, पानी आदि। जिन प्रदेशों में यह सुविधाएँ प्रचूर होती है उन प्रदेशों में उद्योगों का विकास तेजी से होता है। पहाड़ी प्रदेशों में इन सुविधाओं के अभाव में विकास अवरूध्द हो जाता है। भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में संरचनात्मक सुविधाओं की अत्यंत कमी होने से प्रादेशिक असन्तुलन बढ़ा हुआ है।

जनसंख्या का घनत्व :– विभिन्न प्रांतों में जनघनत्व में भी असमानता है, जिसमें अधिक घनत्ववाले राज्य जैसे केरळ, बिहार, उत्तर प्रदेश यह अधिक पिछड़े हुए है। जबकि कम घनत्व वाले राज्य जैसे महाराष्ट्र, तामिळनाडू इनकी तुलना में अधिक विकसित है।

आर्थिक नियोजन की असफलता :– भारत में आर्थिक नियोजन की सभी योजनाओं में एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में प्रादेशिक सन्तुलन को महत्त्व दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही इस समस्या पर जोर दिया गया है परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ती नही हो सकी। नियोजन तंत्र के द्वारा विकसित तथा अविकसित प्रदेशों के बीच सन्तुलन स्थापित नहीं किया जा सका यह हमारे नियोजन तंत्र की असफलता ही है। नियोजन में कम विकसित प्रदेशों की अपेक्षा विकसित प्रदेशों को ही अधिक धन आबंटीत हुआ। प्रथम योजना से सातवीं योजना तक पंजाब तथा हरियाणा राज्य को ही प्रतिव्यक्ति नियोजन व्यय राशि प्राप्त हुई। इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश इन तीन राज्यों को भी अधिक राशि वितरित हुई। परंतु बिहार, आसाम, ओरिसा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान इन राज्यों के हिस्से पर कम राशि आबंटीत हुई।

सार्वजनिक उद्योगों का घटियाँ प्रदर्शन :–भारत सरकार की विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत पिछड़े हुए प्रदेशों में सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की गई, ताकि सन्तुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जैसे राऊरकेला, भिलाई, सिंगभूम, बरौनी आदि प्रदेशों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की गई थी। लेकिन इन प्रदेशों में भारी निवेश के बावजूद भी इन उपक्रमों का प्रदर्शन घटियाँ रहा, अर्थात उन प्रदेशों के उद्योग घाटे में रहे।

हरितक्रांति की असफलता :– देश में सभी प्रदेशों में कृषि उत्पादकता में क्रांति लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हरितक्रांति के कार्यक्रम को अपनाया गया, परंतु यह क्रांति देश के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रही जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों का कृषि उत्पादन बढ़ा परंतु अन्य प्रदेशों में हरितक्रांति का प्रदर्शन निम्नस्तरीय रहा। नई कृषि नीति से आज भी कई प्रदेश अछूते रहे है। बिना सिंचाईवाले प्रदेशों की हालत और भी गंभीर होने से किसानों की आत्महत्या जैसी नई समस्या ने जन्म ले लिया है।

राजनैतिक कारण :– प्रादेशिक असन्तुलन के लिए प्रमुख कारण राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक दूरदर्शिता, उचित नेतृत्त्व का अभाव यह भी कारण जिम्मेदार है। जिसके परिणामस्वरूप हिंसा, कानून

ISSN – 2348-7143

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

The Berar General Education Society's

SITABAI ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, AKOLA

(NAAC Reaccredited "A" grade)

University Grants Commission, Sponsored

One Day National Conference

On 30 January 2018

Economical Study of Regional Disparity in India

Special issue of an International

SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

IMPACT FACTOR SJIF (2016)-6.177

ISSN : 2[illegible]–4766 (P), ISSN : 2278-8808 (E)

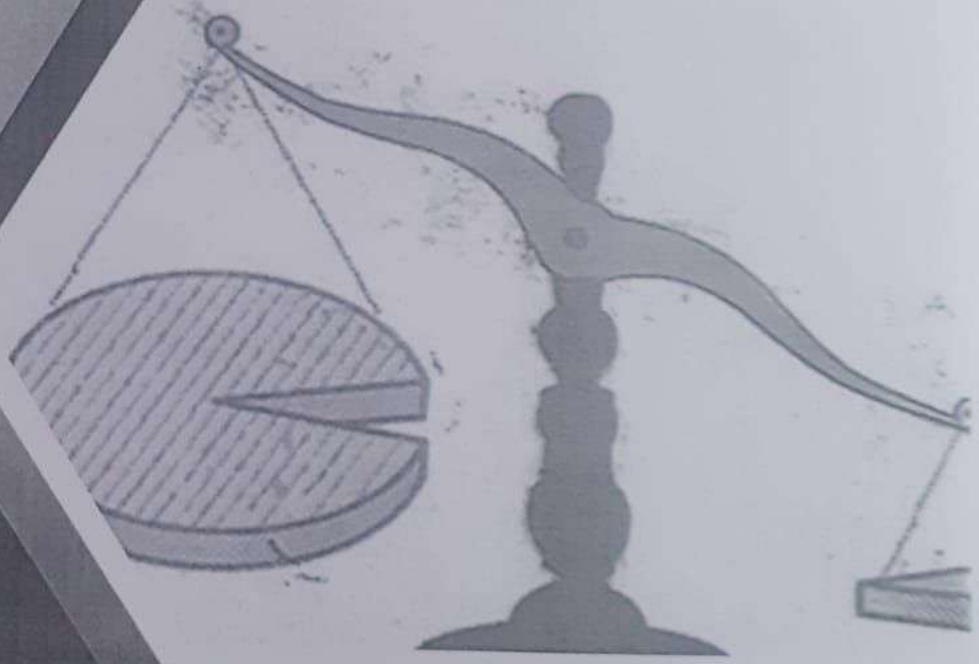

Editor

Dr. Prasannajit R. Gawai

134.

भारत में प्रादेषिक असंतुलन

प्रा. डॉ. रमेश प्रभाकर जोशी

अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, श्री संत गाडगे बाबा हिंदी महाविद्यालय, भुसावल, जि. जलगाँव (महाराष्ट्र)

प्रास्ताविक :– असन्तुलन से आशय क्षेत्र विशेष में उपलब्ध क्षमताओं या संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद उनका विकास न होने से है। एक देश के कुछ प्रांतो को विकसित और कुछ प्रान्तों का पिछड़ा होना अथवा एक ही प्रांत में कुछ क्षेत्रों का विकसित और कुछ कम विकसित होना अथवा एक ही प्रांत में कुछ क्षेत्रों का विकसित और कुछ का पिछड़ा होना प्रादेशिक असन्तुलन कहलाता है। वर्तमान समय मे देश की सबसे प्रमुख समस्या प्रादेशिक असन्तुलन ही है। भारत के विकास में सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता क्षेत्रिय असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रिय असमानता तथा औद्योगिक असमानता ही सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इसे हमें अवश्य समाप्त करना होगा। सामाजिक असमानता के फलस्वरूप आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, बंधुता, मानवता तथा नैतिकता कम होती जा रही है। आर्थिक असमानता के कारण समाज में अरबपतियों तथा अमीरों की संख्या बढ ही रही है लेकिन दूसरी ओर गरीब लोग जिस हाल में थे, आज उसी हालात में है और कुछ लोग अधिक गरीब होते जा रहे है। किसी भी समाज में सामाजिक न्याय की नींव आर्थिक न्याय ही है। आर्थिक समानता के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते। शैक्षणिक असमानता के कारण ही हम समाज में वंचित वर्ग को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल हो रहे है। किसी भी समाज में शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता। क्षेत्रीय असमानता के कारण आज केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों का ही विकास संभव हुआ है। इस पर हमें गंभीरतापूर्ण तरीके से विचार करना होगा। इसी तरह से बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे कई क्षेत्रों में असमानताओं से आम जनता को लड़ना पड़ रहा है। किसी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे बिजली तो कही आज भी लोग लालटेन की रोशनी में जीने को विवश है। इस प्रकार की असमानता समाज को अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही है।

भारत में योजना काल में प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने के लिए सभी योजनाओं में प्रावधान किया गया। प्रथम योजना में यह कहा गया था कि, 'इस योजना में प्रादेशिक सन्तुलन एवं सतत् संवृध्दिपर उचित ध्यान दिया जायेगा।' दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी सन्तुलित प्रादेशिक विकास को आवश्यक बनाता हुए कहा गया था कि, "विभिन्न प्रांतों के बीच विकास के स्तरों में विद्यमान असमानताओं के (क्रमिक) रूप से दूर करना चाहिए। क्षेत्रीय तथा प्रांतीय असन्तुलन के बारे में आठवीं योजना में पुनः चिन्ता व्यक्त कर यह कहा गया कि, "उपलब्ध सूचना से आय तथा धन के संकेद्रण में कमी होने की प्रवृत्ति का कोई संकेत नहीं मिलता।"

यहाँ यह तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि, देश में जहाँ प्रादेशिक असन्तुलन है, वही एक प्रदेश के अंदर में क्षेत्रीय असमानताएँ बहुत अधिक है। अतः नियोजन के लगबग 60 वर्षों के बाद आज भी देश के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक असमानताएँ है। असन्तुलन को, कृषि उद्योग, शिक्षा आदि आधारों पर आँका जा सकता है।

प्रतिव्यक्ति आय :– आर्थिक विषमताओं को मापने का एक सबसे अच्छा मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय है। जिन क्षेत्रों में आर्थिक विकास अधिक हुआ है, वहाँ प्रतिव्यक्ति आय अधिक होती है। इसके विपरीत जो क्षेत्र पिछड़े है, वहाँ प्रतिव्यक्ति आय कम होती है। सन 2014–15 के अनुसार सबसे अधिक प्रतिव्यक्ति आयवाले राज्य तामीलनाडू 176228/–, केरल 172268/–, उत्तराखंड 176663/–, तेलंगना

International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832, (Print) E-ISSN 2320-5474, January, 2014, VOL-V * ISSUE-60

है कि देश में खाद्यान्न की महगाई की गंभीर समस्या है। खाद्यान्नदार्थ स्थानिय स्तर पर खरीदे और बेचे जाते है। उनका बाहर से आयात संभव नहीं है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एक बार बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने पर अपनी मनमानी पर उतर सकती है। वे देश के संसाधनों का अनुचित दोहन कर सकती है। डॉ. भरत झुनझुनवाला का कहना है कि हमें एफ. डी. आय. के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। वह हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा।

उपभोक्ताओं को हानि :–

विदेशी रिटेल बिझनेस मॉडेल बड़े रिटेल स्टोअर फॉर्मेटपर आधारित है। इनकी ऊर्जा की की खपत बहुत अधिक है, ए. सी. तथा अन्य सुविधाओं के कारण इनके खर्चे बड़े होते है। यह स्टोअर्स अमीरी और विलासिता पर निर्भर जीवन शैली को बढ़ावा देते है। यह जीने की तथा शॉपींग की अमेरिकन शैली है, भारतीय नहीं। कम्पनियों के इन सभी खर्चों का बोझ आखिर उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। जाहीर है कि उपभोक्ताओं को ऊँचे दामों पर उपभोग करना होगा। अतः सरकार को इन कम्पनियों की योजनाओं पर ध्यान देना होगा।

शोषण की वृत्ति बढ़ेगी :–

कई विकसित देशों में खुदरा कारोबार कम्पनियों पर श्रमिकों एवं कर्मचारियों के शोषण, एकाधिकारी प्रवृत्ति, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन, पर्यावरण को हानि पहुँचाने तथा समाज में अति उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप लगाये जा रहे है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वृति शोषण की है, जिससे श्रमिकों तथा किसानों के शोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

भ्रष्टाचार एवं विषमता बढ़ेगी :–

एफ. डी. आय. को लागू करने का फैसला केन्द सरकार ने कुछ हद तक राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। सरकारी अधिकारियों तथा वैश्विक कारोबारियों के बीच एक नया समीकरण बन जायेगा। इसे प्रवृति को राजनेताओं द्वारा भी सहायता की जायेगी। रिटेलरों के आपसी रस्साकशी में मुकाबलाखोरी तथा अतिबाजारवाद की वृत्ति बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार एवं पूँजीगत विषमताएँ और अधिक बढ़ेगी। भारतीय विद्वानों का मत है कि भारतीय कालाधन विभिन्न मार्गों से देश के बाहर जाता है और वही कालाधन एफ. डी. आय. के रूप में देश में वापिस आ रहा है। 80 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में कालाधन ही है। अतः यह भ्रष्टाचार, जमाखोरी एवं काले धन को बढ़ावा देने वाला कदम है।

बेरोजगारी :–

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत के 130 करोड़ लोगों वाले सबसे बड़े बाजार की ओर आकर्षित है। उनके पास साधन बहुत है। वे बड़े पैमाने पर खरीदारी करेगें और कम दामों पर सामान बेचेगें। वॉलमार्ट जैसी कम्पनियाँ अनेक देशों में यही कर रही है। इसलिए दुनियाभर में इन कम्पनियों के विरोध में आन्दोलन भी हुए है। बहुराष्ट्रीय निगमों का खुदरा बाजार क्षेत्रपर एकाधिकार स्थापित होगा। उनके सामने छोटे–मोटे रिटेल कारोबारी टिक नहीं पायेंगे। इन स्टोअर्स के आसपास के व्यवसाय बन्द हो जायेंगे। परिणामस्वरूप कई लोग बेरोजगारी का शिकार हो सकते है।

निष्कर्ष (Conclusion):–

एफ. डी. आय. पर्यावरण संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती है। अतः सरकार को केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। आर्थिक तथा पर्यावरण के स्तर पर नियामक बनाकर इन कम्पनियों के कारोबार पर निगरानी रखनी चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम भी उठाने चाहिए। भ्रष्टाचार, एकाधिकार वृति, जमाखोरी तथा काले धन पर अंकुश रखना परम आवश्यक है, तभी एफ. डी. आय. से लाभ होगा।

संदर्भ ग्रंथ

1) भारतीय अर्थशास्त्र – रुद्रदत्त एवं सुंदरम्
2) हितवाद न्यूज पेपर – 9 जानेवारी 2014
3) प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल 2012, मई 2013
4) द न्यूज चैनल
5) हिन्दुस्थान टाईम्स न्यूज
6) स्थानिय समाचार पत्र
7) रिजर्व बैंक बुलेटिन 2012
8) प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट 2012
9) असिस्टंट प्रोफेसर : नारायण सेटी, राउरकेला रिपोर्ट
10) करंट अफेयर्स – दैनिक भास्कर, देविंदर शर्मा
11) मनोरमा ईयर बुक 2012
12) इंडिया – 2011–12

स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी, दक्ष और कार्यकुशल बनेगा। विदेशी कम्पनियाँ तथा घरेलू खुदरा कारोबार एक दूसरे के साथ–साथ आगे बढ़ेगें।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले लाभ :–

अधोरचना का विकास :– भारत में आर्थिक विकास में एक प्रमुख बाधा संरचनात्मक सुविधाओं की कमी होना है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से परिवहन, ऊर्जा, प्रशीतन, प्रसंस्करण, भण्डारण, शीत श्रृंखला तथा विपणन संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। परिणाम स्वरूप एक ओर उत्पादन की लागतें कम होगी तो दूसरी ओर मुद्रा स्फीति कम होने से उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होगें।

उत्पादन में वृध्दि :–

एफ. डी. आय. से खुदरा व्यापार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ेगा। उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार होगा। भारत में सन 1990 के बाद वस्तु उत्पादन की गुणवत्ता बढी है। आधुनिक तकनीक के कारण अर्थव्यवस्था गतिशील और प्रतियोगी बनने में मदद मिल रही है। मानव संसाधन अधिक कार्यकुशल एवं गुणवत्तापूर्ण होगा तथा हमारी लाइफ स्टाइल भी बदलना संभव है।

खाद्यान्नों की बर्बादी रूकेगी :–

एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष 15 से 20 प्रतिशत कृषी उपज भण्डारण तथा प्रशीतन के अभाव में बर्बाद होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से अच्छे भण्डारण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग तथा विपणन व्यवस्था में सुधार होने से कृषी उत्पादनों का अधिक गुणवत्तापूर्ण और समुचित ढंग से उपयोग किया जा सकता है। रिटेल स्टोअर्स सीधे किसानों से फल, सब्जियॉ तथा खाद्यान्न की खरीदारी करेंगे जिससे किसानों का नुकसान कम होगा।

तकनीकी लाभ :–

खुदरा क्षेत्र में एफ. डी. आय. का सबसे प्रमुख लाभ तकनीकी लाभ है। विश्व की आधुनिक तकनीक देश में आने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान समय में कम्प्युटर, इंटरनेट, मोबाईल, कार, मोटार साइकिल, इलेक्ट्रानिक्स तथा उपभोग के क्षेत्र में नई तकनीकी परिवर्तन के कारण उपभोक्ता वर्ग को अच्छी किस्म की वस्तुऍ उपभोगने को मिल रही है। साथ ही व्यापार में भी विस्तार हुआ है। कृषी यंत्र तथा तंत्र, नये किस्म के बीज, रसायनों तथा खादों का प्रयोग बढ़ेगा। इंजिनिअरिंग तथा औद्योगिक क्षेत्र को भी तकनीकी लाभ प्राप्त होंगे।

रोजगार वृध्दि :–

देश में रोजगार की बड़ी समस्या है। एफ. डी. आय. के कारण लघु तथा कुटीर उद्योगों के साथ–साथ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों कृषी और औद्योगिक गतिविधियॉ बढ़ेगी। खुदरा व्यापार क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं के बढ़ने से रोजगार की नई संभावनाऍ उत्पन्न होगी। देश के खुदरा व्यापार क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होने का अनुमान है। यह निश्चित ही भारत के लिए अच्छा लाभ कहा जा सकता है। इतने लोगों को रोजगार प्राप्त होने से उनकी आय तथा उपभोग भी बढ़ेगा।

किसानों की स्थिति में सुधार :–

भारत में किसानों में गरीबी, ऋणग्रस्तता, अज्ञानता, तकनीकी, पिछड़ापन तथा साख की कमी आदि कई समस्याऍ विद्यमान है। एफ. डी. आय. से किसानों की उपज का उचित श्रेणीकरण तथा प्रमापीकरण होगा। शीतगृहों तथा भण्डारण सुविधाओं में सुधार होने से किसानों को होनेवाले नुकसान से बचाया जा सकता है। देश में किसानों में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याऍ बढ़ी है। इन सभी समस्याओं के समाधान का एक उपाय एफ. डी. आय. हो सकता है।

व्यापार में वृध्दि :–

एफ. डी. आय. से ग्रामीण तथा छोटे शहरों में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में वृध्दि होगी। छोटे–छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण उत्पादन बड़े शहरों तथा विदेशों में भी पहूँचने की संभावना उत्पन्न होगी। बाजार में व्यापार के साथ–साथ पूँजी का प्रवाह भी बढ़ेगा। जिससे व्यक्तिगत आय में वृध्दि होगी। इस तरह के कई लाभों से एफ. डी. आय. का समर्थन किया जाता है।

एफ. डी. आय. से उत्पन्न होने वाले दोष :–

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, परंतु फिर भी एफ. डी. आय. के कारण उत्पन्न होनेवाले दोषों की ओर दुर्लक्ष नहीं किया जा सकता।

घरेलू उद्योगों को हानि :–

भारत में अभी भी तकनीकी और गुणवत्ता के आधार पर वैश्विक मानदण्डों के अनुसार घरेलू खुदरा व्यापार में प्रतियोगिता का मोहाल नहीं है। ऐसी स्थिति में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को तुरंत विस्तारित स्तर पर अनुमति देने से खुदरा व्यापार के साथ घरेलू उद्योगों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः सरकार को सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता है। देश में घरेलू उद्योगों को प्रतियोगिता के लिए सक्षम बनाना होगा। अन्यथा घरेलू उद्योगों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगेगा।

किसानों को हानि :–

कॉर्पोरेट लॉबी के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इससे देश के किसान वर्ग को लाभ होगा परंतु वास्तविकता यह है कि बिचोलियों तथा व्यापारी वर्ग के चैन के कारण किसानों को उनके फसलों के उचित दाम मिल नहीं पाते। भारतीय कृषी उत्पादन से संबंधित कानून भी काफी पूराने है। संगठित रिटेल से इस समस्या को हल करना कठिन होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सहारे किसानों को अधिक समय तक रखना कठिन होगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किसानों का शोषण भी होने की संभावना है।

महंगाई की समस्या :–

एफ. डी. आय. के समर्थन मे यह भी कहा जाता है कि संगठित रिटेल से महंगाई कम होगी। परंतु वास्तविकता यह

An International Indexed, Refereed, Interdisciplinary, Multilingual, Monthly Research Journal
ISSN 0974-2832
Issue-60, Vol-V, January-2014
Impact Factor-1.0060 UIF.

SHODH SAMIKSHA AUR MULYANKAN

शोध समीक्षा और मूल्यांकन

Dr Ram Joshi

S.S.M.
WAY TO SUCCESS.....
R.A.E.
AN INTERNATIONAL REFERRED RESEARCH JOURNAL
JAIPUR INDIA

Editor
Dr. KRISHAN BIR SINGH

www.ssmrae.com

लोगोंके लिए रोजगार के अवसर काफी कम हो गए है.

7. माँग में कमी :- अमेरिकाके वॉलस्ट्रीट सहित दुनियाभर के शेअरबाजारोंमें सूचिबध्द कंपनियों के शेअरों में गिरावट दर्ज होनेपर वैश्विक मंदी की वास्तविकता सामने आयी है. दुनियाभर की सॉफ्टवेअर कंपनिया, रियल इस्टेट क्षेत्र, टेक्सटाईल, अधोरचना, हवाईसेवा, बैंकिंग सेवा तथा पर्यटन क्षेत्र आदी क्षेत्रोंपर बुरा प्रभाव पडने से संकटग्रस्त कंपनियोंमें वेतन तथा उत्पादन में कटोती के साथ साथ नोकरीयोंको घटाने का दौर भी शुरू हुआ है. इसका बुरा असर बाजारोंपर देखनेको मिला है. लोगोंद्वारा बाजारोंमें वस्तुओंकी माँग कम होने लगी है. होटल, रेस्टॉरंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा शोरूम ग्राहकोंकी राह जोहने लगे है. कई बडे उद्योगपतीयों ने अपने अरबों डॉलर गवाए है. भारत के शीर्श 10 उद्योगपतीयों की बात करें तो 2008 के दौरान उन्होंने 130 अरब डॉलर गवाऐं है. 28 अक्तूबर 08 का दिन वैश्विक पूँजी बाजार के लिए काला दिन साबीत हुआ है. ग्लोबल रेटिंग एजन्सी तथा वित्तीय आकडों को उपलब्ध करानेवाली स्टॅंडर्ड ॲन्ड पुअर्स के अनुसार वैश्विक मंदी के चलते 2008 में निवेशकोंको लगभग 11 हजार अरब डॉलर की हानी उठानी पड सकती है.

8. भुगतान संतुलनपर बुरा प्रभाव :- वैश्विक मंदीने भारत के व्यापार संतुलन तथा भुगतना संतुलन को भी बुरी तरहसे प्रभावित किया है. रिझर्व बैंक के अनुसार 2008 की पहली तिमाही मे चालू खाते का घाटा 14.64 अरब डॉलर रहा है. तथा भुगतान संतुलन में कूल घाटा 17.88 अरब डॉलर रहा है, जो पिछले साल की तुलना में अधीक है, अर्थात भारत के भुगतान संतुलनपर वैश्विक मंदीका गहरा बुरा प्रभाव पडा है.

सुझाव (Suggestions) :- वैश्विक मंदी और सामान्य आदमी

वैश्विक मंदी के परिप्रेक्षमें हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए की, जिससे हम मंदी के प्रभाव से कम से कम प्रभावित हो सके. हमारी नजरमें इस मंदी की स्थितीमें निम्न बातोंपर अमल करना आवश्यक हैं.

1. मंदी की इस स्थितीमें हमें कम से कम ऋण लेने चाहिए, विशेष कर मकान आदी प्रॉपर्टी की खरिदारी नकद रुपसे करनी चाहिए. 2. हमें अपने सभी प्रकार के ऋणों के भुगतान की अदायगी नियमित और आवश्यक रुप से करनी चाहिए. 3. मंदी के इस दौर मे शेअर मार्केट तथा अन्य नयी खरीदारी को कम से कम करना चाहिए. 4. मंदी के इस दौर मे कोई भी निवेश सोच समझकर तथा परखकर करना चाहिए. 5. मंदी के इस वातावरण में इस समय प्रॉपर्टी आदी संपत्ती को बेचना लाभदायक हो सकता है. 6. हमें आरामदायक खर्चों तथा अन्य अनावश्यक खर्चोंपर प्रतिबंध लगाना चाहिए. 7. वर्तमान परिस्थिती मे अपना वर्तमान व्यवसाय या नोकरी को नही बदलना चाहिए. 8. मंदी का सामना करने के लिए हम सभी को सरकारी की नीतियोंका समर्थन और सहयोग करना चाहिए. 9. आर्थिक बातोंके साथसाथ हमें अपने स्वास्थ्य की ओरभी विशेश रुप से ध्यान देना चाहिए.

इस तरह से कुछ आवश्यक कदम उठाकर हम मंदी की मार से बच सकते है.

निष्कर्ष (Conclusion) :- उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विकरण ने इस मंदी की आंधी को सारे विश्व मे फैलानेमें अपना बडा योगदान दिया है. वैश्विक मंदी के कई गंभीर प्रभाव विभिन्न देशोंको भुगतने पड रहे है. विश्व के विभिन्न देशोंने अमेरिकी कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं में भारी मात्रा में निवेश किया है, इसलिए वे सभी इस लहेर की चपेट मे आ गए है. इसके बावजूद भी भारत में वृध्दी दर 2008–09 के विश्व बैंक के अनुसार 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वास्तव में इससे भी अधिक अर्थात 6.7 प्रतिशत रही है. यह हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूती का लक्षण है. भारत मे मंदी की मार कम रहने का एक प्रमुख कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का कृशी व्यवसायपर निर्भर होना है. इसलिए हमें अपने कृशी व्यवसाय की ओर दुर्लक्ष नही करना चाहिए बल्कि उसके विकास की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए. मंदी के लिए विकसित देशों की फिजुलखर्चीही जिम्मेदार है. अत: हमें अपने गिरेबान में झाँकना पडेगा और अपने अनियंत्रित खर्चों तथा उपभोगवादी प्रवृत्तीपर लगाम लगाकर पुंजीवाद की अपेक्षा मिश्र अर्थव्यवस्थाकोही अपनाना चाहिए ऐसा मेरा मत है.

संदर्भ ग्रंथ

* आर्थिक समिक्षा 2008–09 *रिझर्व बैंक बुलेटिन 2008–09 *जी–20 शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट *प्रतियोगिता दर्पण वार्षिक अगस्त 2009 *रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी 2008 09 *जागतिक *केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के आंकडे *वैश्विक विकास वित्त रिपोर्ट 2009 *स्थूल अर्थशास्त्र – म. ना. दाबरे *जागतिक मंदी–स्वरूप व उपाय – डॉ. जे. एफ. पाटील अर्थव्यवस्था – मधुसुदन साठे

International Indexed & Refereed Research Journal, ISSN 0974-2832, (Print) E-ISSN 2320-5474, January 2014, VOL-V *ISSUE-60

शोध पत्र —अर्थशास्त्र

भारत के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाभ एवं दोष

* प्रा. डॉ. जोशी रमेश प्रभाकर

January, 2014

*असोसिएट प्रोफेसर एवं अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, श्री संत गाडगेबाबा हिंदी महाविद्यालय, भुसावल (महाराष्ट्र)

सारांश (Abstract):– केन्द्र सरकार के द्वारा उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के तहत विदेशी निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। टेलिकॉम, डिफेन्स, ऑयल रिफायनरीज, खुदरा बाजार, ऊर्जा क्षेत्र तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे क्षेत्र में एफ. डी. आय को खुली छूट दी गयी है। वास्तव में यह भारत के विकास को अस्थायी सपोर्ट लिया जा रहा है। देश के स्थायी विकास के लिए यह उचित नहीं है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, स्थानिय विरोध, भू–संपादन की समस्या, राजनेताओं का हस्तक्षेप तथा महंगाई जैसी – कई समस्याएँ विद्यमान है। एफ. डी. आय. के लाभों के साथ–साथ कुछ गंभीर दोष भी है। जिनकी ओर दुर्लक्ष नहीं किया जा सकता। डॉ. भरत झुनझुनवाला के मतानुसार हमें 80 प्रतिशत एफ. डी. आय. काले धन की वापसी है जो भारत से ही बाहर गया हुआ है। देश की पूँजी का प्रवाह बाहर देशों की ओर प्रवाहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने ही देश में पूँजी निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। घरेलू खुदरा क्षेत्र में लगे व्यापारी तथा निवेशकर्ताओं को प्रेरित करना चाहिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारत के दूध के व्यवसाय में अमूल ब्रांड ने कमाल किया है, ऐसे ही फल, सब्जियों एवं अन्य कृषी उत्पादों में भी हो सकता है।

प्रस्तावना (Introduction):–

नये आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार के क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 5 दिसंबर 2012 को मंजुरी प्रदान की है। इस के साथ ही देश के 590 अरब डॉलरवाले खुदरा क्षेत्र में वॉलमार्ट, केरफोर, टेस्को, मेट्रो एजी, आईकिया जैसी कम्पनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। निश्चित ही यह एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। सरकार के इस क्रांतिकारी निर्णय का विश्वभर में स्वागत भी हुआ है। कहा जाता है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह कदम लाभकारी होगा। लगभग 50 प्रतिशत एफ. डी. आय. भारत, चीन, ब्राझील तथा चीन (ब्रीक) देशों में होगा। इन देशों की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन विकसित देशों की अपेक्षा बहुत अच्छा रहने की संभावना है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में घरेलू माँग काफी मजबूत बनी हुई है। देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप (LLPs) फर्मों में भी अनुमति दी है।

प्रारंभ में ऐसे खुले क्षेत्रों में कार्यरत फर्मों में ही एफ. डी. आय. को अनुमति मिलेगी जिनमें विदेशी निवेश के निगरानी की आवश्यकता नहीं रहेगी। कृषि बागान, प्रिंट मिडिया एवं रियल इस्टेट आदि में संलग्न लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप में विदेश निवेश की अनुमति नहीं होगी परंतु उसके लिए विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजुरी लेनी पडेगी।

संशोधन पध्दती :–

विद्यमान लघु शोध निबंध के अध्ययन में संशोधन की द्वितीयक अध्ययन पध्दति को स्वीकार किया है। इस निबंध के अभ्यास के स्त्रोत संदर्भ ग्रंथ, किताबों, विभिन्न मॅगझीन्स, न्यूज पेपर्स के लेख, तथा विभिन्न खबरें आदि प्रमुख है। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी तथा अपने स्वयं के विचारों का यथोचित उपयोग किया गया है।

भारत के संदर्भ में खुदरा कारोबार में एफ. डी. आय. की आवश्यकता :–

भारत के संदर्भ में विचार करने योग्य बात यह है कि क्या देश का घरेलू बाजार इतना मजबूत है कि वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ चुनौतियों का मुकाबला कर पायेगा? इस प्रश्न का जवाब शायद नही है। प्रत्येक देश में खुदरा व्यापार वह अन्तिम कडी है, जहाँ से सीधे ग्राहकों को वस्तुएँ उपभोगने को मिलती है। यह व्यापार अत्यंत विस्तृत होता है। अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी नीलसन के अध्ययन के मुताबिक भारतीय उपभोक्ताओं का पूरी दुनिया में सबसे अधिक विश्वास है। इस बाजार में व्यापार की संभावनाएँ अधिक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इस बाजार पर अपनी मजबूत पकड बनाने की ठान ली है। देश में कृषि के बाद खुदरा व्यापार पर ही सर्वाधिक लोग निर्भर है। एक अनुमान है कि देश में करीब 3 करोड खुदरा व्यापार के पटल है जिसमें 30 से 35 करोड लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

भारत की 65 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र आश्रित है। दुनिया में भारत दूध के उत्पादन में अव्वल स्थान पर है और फल–सब्जी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। देश में प्रतिवर्ष कुल कृषि उत्पादनों का उन्नीस से बीस प्रतिशत हिस्सा उचित रखरखाव, विपणन व्यवस्था, शीत श्रृंखला, सुरक्षा, बिजली की कमी, तथा यातायात जैसी सुविधाओं के अभाव में बर्बाद हो जाता है। दूध, सब्जी, फलों में यह नुकसान 40 प्रतिशत है। किसानों को मध्यस्थों के कारण उपज के उचित दाम नहीं मिलते। अधिकांश लाभ बड़े व्यापारी, बड़े किसान, बिचोलिए ही उठा लेते है। भारत में खाद्यान्न तथा शीघ्र नाशवान पदार्थों के प्रसंस्करण की सुविधायें अत्यल्प है। विज्ञान, शिक्षा, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, परिवहन आदि सुविधाओं में भी भारत पिछड़ा हुआ है। एफ. डी. आय. से घरेलू खुदरा व्यापार, उत्पादन प्रबंधन, गुणवत्ता तथा विपणन के

SHRI SANT GADGE BABA HINDI MAHAVIDYALAYA

वैश्विक आर्थिक मंदी तथा उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुए प्रभाव

*प्रा. डॉ. रमेश प्र. जोशी

प्रस्तावना-इस वैश्विक सुस्ती का सर्वाधिक प्रतिकुल प्रभाव आफ्रिकी, केंद्रीय एवम् पूर्व लॅटीन अमेरिका देशोंपर पडा हुआ है. तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था जैसे की भारत तथा चीन पर वैश्विक मंदी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा है. सकल रूप से वैश्विक सकल घरेलु उत्पाद के वर्श 2009 में घटकर 2.9 प्रतिशत रहने की संभावना है, तथा विश्व व्यापार में 10 प्रतिशत की कमी आ सकती है. एशिया में वैश्विक मंदी का सबसे घातक प्रभाव थायलैंड पर पडा है. विश्वबैंक की आशंका है की, सन 2009 में विकासशील देशोंमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. कुछ विद्वानों का यह मत है की, यह समझ लेना चाहिए की, इसके जैसा संकट इसके पहले कभी पैदा नही हुआ है. वैश्विकरण ने इस मंदी को सारे विश्व में फैलाने में अपना योगदान दिया है. अर्थशास्त्रीयोंके मतानुसार मुद्रास्फीती ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन मुद्रा संकुचन नही. वैश्विक मंदी का संकट शिखरपर पहुंच चुका है. सितंबर, अक्तूबर 2008 में जब अमेरिका के वित्तीय क्षेत्र की नामी, गिरमी कंपनियॉ दिवालिया होने लगी या बिकने लगी तथा विकसित देशों सहीत भारत में शेअरों की किमतों में भारी गिरावट हुई. भारत में मुंबई स्टॉक एक्चेंज का संवेदी सूचकांक 22000 के स्तर से गिरकर कुछ ही दिनों में 9000 के स्तर पर पहुॅच गया. शेअर बाजार में गिरावट का दौर आते ही विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बडे पैमाने पर बिकवाली प्रारंभ कर दी तथा कुछ ही दिनों में भारत से करोंडो डॉलर की पूंजी पलायन कर गई. इसके परिणाम स्वरूप उद्योगोंकी कार्यकुशलता में गिरावट तथा बेरोजगारी जैसे गहरे संकटों का खतरा बन गया. वैश्विक सुस्ती के कारण निर्धन देशोंके बेरोजगारी तथा बडी संख्या में लोगोंके निर्धनता मकडजाल में फस जाने की आशंका बनी हुई है. संभवतः विगत दो दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है की, निरपेक्ष तथा सापेक्ष निर्धनता दोनों के प्रसार में वृध्दी हो रही है.

पध्दती (Methods) :- प्रस्तुत शोध निबंध के लिए संशोधन की द्वितीयक पध्दतीका उपयोग किया गया है. किताबों, मॅगझीन, न्यूज पेपर तथा संदर्भ ग्रंथों से समस्त जानकारी संकलित कर उसका यथोचित उपयोग किया गया है.

वैश्विक मंदी के संकट के लिए उत्तरदायी कारण:- वित्तीय बाजारोंके घराशायी होने तथा वैश्विक मंदी का मूल 2003–04 की तेजी में छिपा हुआ है. इस अवधी में वैश्विक विकास दर 5 प्रतिशत हुई थी जो 1970 के दशक के बाद से सर्वाधिक पोशनिय दर रही है. इस समय विकासशील देशोंके पूंजी प्रवाह में रिकॉर्ड स्तर की वृध्दी दर्ज हुई है.

वैश्विक मंदी के लिए निम्नकारण उत्तरदायी है :-

1. **पुर्नभुगतान क्षमता के आकलन के बिना बडे पैमाने पर उधार देना:-** वैश्विक मंदी के लिए जिम्मेदार तत्वोंमें प्रमुख यह है की, अमेरिका जैसे देश में बडे बडे उद्योगों को उनकी पुर्नभुगतान क्षमता का स्पष्ट आकलन किए बिनाही उन्हे अधिक ऋण या उधार दिया गया. जिसके कारण ऐसे ऋणों की अदायगी एक बडी समस्या बन गयी. पिछले कुछ वर्शों के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपने आपको ऋण देने की नीतिपर केंद्रित कर लिया गया. जिसमें अधिकतर हिस्सा आवास ऋण का था. लोगोंको मुक्त भावसे ऋण बाटनें का परिणाम यह हुआ की, ऋणों की वसुली पूर्ण नही हुई और बैंक तथा वित्तीय संस्थान डूबने लगे.

2. **कमजोर निवेश निर्णयन :-** वैश्विक मंदी का एक कारण गलत तरीकेसे निवेश निर्णयन है. अमेरिकी उद्योगपतीयों और वित्तीय संस्थानों ने विकासशील देशोंमें भारी निवेश किया था. उन्होंने अपनी पूजी हटाने से इन विकासशील देशों की परियोजनाएँ और आद्योगिक गतिविधीयॉ रुक जानेसे भी आर्थिक संकट बढता गया.

3. **निजी वास्तविक ब्याजदरों एवम् पर्याप्त तरलता के बारेमें अतिविश्वास तथा सुखाभास :-** मंदी के लिए जिम्मेदार एक कारण यह है कि ऋणों की नीची ब्याजदरे और पर्याप्त तरलता की ओर दुर्लक्ष किया जाना है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों का अतिविश्वास तथा सुखाभास में रममाण होना है.

4. **बैंक प्रशासन की दुर्बलताएँ :-** वैश्विक मंदी का एक प्रमुख कारण यह है कि, बैंकिंग प्रशासन की लापरवाही तथा निर्णय लेने की कठोर क्षमता का अभाव होना है. अचानक उत्पन्न हुए इस संकट ने बैंको तथा वित्तीय संस्थानों के अस्तित्व पर गहरा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है. दिसंबर 2007 से उत्पन्न सबप्राईम संकट के चलते अमेरिका के लगभग 20 बडे वित्तीय संस्थान दिवालियॉ हो चुके है. अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को सॉस लेनाभी मुश्किल हुआ है.

5. **यूज ॲन्ड थ्रो वाली नीति :-** वैश्विक मंदी का अध्ययन किया जानेपर यह प्रश्न उठता है कि, इस वित्तीय संकट

*श्री संत गाडगेबाबा हिंदी महाविद्यालय, शास्त्री विद्यानगर संकुल, शिवाजीनगर, भुसावल

…haraj, Nagpur University Nagpur)

ISSN 0974-2832

MARCH - 2010 Vol.II, Issue - 14

AN INTERNATIONAL LEVEL REFERRED REGISTERED RESEARCH JOURNAL

SHODH SAMIKSHA AUR MULYANKAN

शोध समीक्षा और मूल्यांकन

Hindi, English, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Information Technology, Engineering, Management, Commerce, Life Sciences, Home Science Economics, Political Science, Public Administration, Education, Music, Law, Human Science, History, Computer, Psychology

AN INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL
S.S.M.
A WAY TO SUCCESS
R.A.E.
JAIPUR INDIA

Editor
Dr. KRISHAN BIR SINGH

www.ssmrae.com

के लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रश्न के जबाब में यह कहना उचित होगा कि, अमेरिका और युरोप के देशोंकी नीति युज ॲन्ड थ्रो कि है, इसके अलावा कुछ भी नही है. जबतक काम आया तो पुरी दुनिया में उदारीकरण का ढिंढोरा पिटा और खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था की वकालत की, जब अपना उद्देश पुरा हुआ तो संरक्षणवाद अपनापर विकासशील देशोंको डूबने के लिए भगवान भरोसें छोड दिया.

6. **वृहत आर्थिक असंतुलन :-** अमेरिकी तथा युरोपियन देशोंमें आर्थिक असंतुलन होने से अनेक आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हुई है. इसके परिणाम स्वरूप यह अर्थव्यवस्थाए स्वयं ही अपने मकडजाल में फस गयी है, ऐसा कहना अनुचित नही होगा.

7. **नियंत्रण का अभाव :-** वैश्विक मंदी के कारणों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि, विनियामक असफलताए जिम्मेदार है. अमेरिकी तथा युरोपियन देशोंमें बैंकिंग और वित्तीय संस्थानोंकी कियाकलापोंपर उचित नियंत्रण अर्थात विनियामक व्यवस्था न होने से यहाँ बैंकिंग प्रणाली बेकाबू हो गयी और वैश्विक मंदीसे गंभीर समस्या का उद्‌गम हुआ है.

8. **देशोंकी निर्भरता :-** वैश्विक मंदी का एक कारण यह है कि आज विश्व का प्रत्तेक देश किसी न किसी रुप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुडा हुआ है, इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी मंदी की मार इन देशोंकोभी झेलनी पडी है.

इस तरह से मंदी के कई कारण बताये जा सकते है.

वैश्विक मंदी के परिणाम :- अमेरिका से शुरू हुई मंदी के अमेरिका, युरोपियन देशोंके साथसाथ भारत जैसे विकासशील देशोंकी अर्थव्यवस्थापर गंभीर दुश्परिणाम हुए है. इन परिणामोंकी चर्चा निम्न प्रकार से की जा सकती है.

1.औद्योगिक उत्पादन में गिरावट :- वैश्विक मंदी का प्रभाव विनिर्माण क्षेत्र तथा उनके वैश्विक व्यापार पर पडा हुआ है. 2008 के अंतीम त्रैमास में वैश्विक उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है. सालाना रूप से 21 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी है. जनवरी 2009 में विकासशील देशों में 2.3 प्रतिशत तथा विकसित देशों में 17.3 प्रतिशत से औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है. पुंजीगत वस्तुओंका उत्पादन करनेवाले विश्व के देशोंमें जापान में 34 प्रतिशत, जर्मनी में 22 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया में 12 प्रतिशत की गिरावट हुई है. भारतमेंभी लगभग 8 प्रतिशत के आसपास यह गिरावट दर्ज की गयी है.

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी गिरावट :- विश्व बैंक के मतानुसार 2009 में विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 30 प्रतिशत की गिरावट होगी ऐसा अनुमान है, ऐसा होने का प्रमुख कारण यह है कि, बहुराष्टीय कंपनियोंद्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकी स्थिती के पैमानेपर स्थायी तथा अंतराल आस्थीयोंमें निवेश करना है. लगभग सभी बहुराष्टीय कंपनियोंकी लाभप्रदता में कमी आयी है. वैश्विक स्तर पर वस्तुओंकी किमतोंमें हो रही गिरावट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को हतोत्साहित किया है. उर्जा क्षेत्र की अनेक कंपनियोंने अपनी निदेश योजनाओंको सिमित कर दिया है. वैश्विक निवेशक प्राय: विकसित देशों में राष्टीयकरण की नीतियोंको लेकरभी आशंकित है. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्शित करने में भारत का स्थान 13 वा रहा हैं, अर्थात भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आयी है.

3. संसाधनोंकी कमी :- विश्व बैंक के आंकडे दर्शाते है कि इस वित्तीय संकट के कारण विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर मौद्रीक प्रवाह, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलिओ निवेश, अनुदान एवम् सहायता आधे से भी कम रह गए है. विश्व के निर्धन देश अपेक्षाकृत लंबी अवधी तक आर्थिक मंदी में फसें रहेंगे, क्योंकि इन देशों की सार्वजनिक एवं निजी कंपनियोंके पास वांछित संसाधन नही होंगे. भारत में संसाधनों की कमी पहलेसेही होने से यह संकट और भी गहरा हुआ है.

4. सकल घरेलु उत्पाद में गिरावट :- वैश्विक मंदी के कारण समग्र रुप से घरेलु उत्पाद में 2009 में घटकर 2.9 प्रतिशत रह जाने की संभावना है, तथा विश्व व्यापार में 10 प्रतिशत की कमी आ सकती है. युरोप तथा एशिया में 5 प्रतिशत की कमी आएगी. भारत जैसे देशों के विदेशों में कार्यरत श्रमिकोंद्वारा स्वदेश भेजे जानेवाले अंतरणों एवम् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारी गिरावट आयी है. एशिया में वैश्विक मंदी का सबसे घातक प्रभाव थायलैंड पर पडा है. भारत के सकल घरेलु उत्पाद में लक्षणीय गिरावट देखी गयी है.

5. विदेशी व्यापार में गिरावट :- वैश्विक मंदी के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नही रहा है. विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी रुप से अमेरिका के बाजार से जुडा हुआ है, जिसके परिणामस्वरुप अमेरिका के साथ साथ इन देशों के विदेशी व्यापार में भी गिरावट दर्ज हुई है. आर्थिक समिक्षा के अनुसार भारत में 2008–09 के लिए 200 अरब डॉलर का निर्यात का लक्ष निर्धारित था, जो घटकर 175 अरब डॉलर रहा है, परंतु वास्तव में यह केवल 168.7 अरब डॉलर ही रहा है. जो गत साल की तुलना में 3.6 प्रतिशत की वृध्दी दर्शाता है. भारत का निर्यात 25 प्रतिशत से भी अधिक घटा है. वैश्विक मंदी के कारण भारत के निर्यातों में संवृध्दी दर काफी कम रही है. भारत की निर्यात में बडा हिस्सा रखनेवालें रत्न एवम् आभूशण उद्योग, टेक्सटाईल एवम् रेडिमेड वस्त्रोंकी हजारों इकाईयॉ बंद हो चुकी है.

6. बेरोजगारी :- वैश्विक मंदी का सबसे बडा असर रोजगार पर हुआ है. भारत जैसे विशाल जनसंख्यावाले देशमें बेरोजगारी की समस्या पहले से ही गंभीर है, वैश्विक मंदी ने इस समस्या को अधिक व्यापक बना दिया है. रत्न, आभुशण, वस्त्रोद्योग की लाखों इकाईयॉ बंद हो जाने से कई लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पडा है और जो लोग विदेशों में नौकरी हेतू गए थे उनमें से कई लोग अपने देशमें वापस आए है. इसका परिणाम यह हुआ की, भारत में बेरोजगारी कि समस्या और अधिक गंभीर बन गयी. विदेशों में भारतीय